

दमघौंट हवा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती- अब नियमित सुनवाई से जुड़ेगी दिल्ली की सांसों की लड़ाई

दिल्ली एन्सीआर की हवा इन दिनों सिर्फ प्रदूषण नहीं, बल्कि जीवन पर सीधा आक्रमण करती हुई महसूस हो रही है। ऐसे विषाक्त माहौल में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कठोर रुख अपनाया है। अदालत ने यह साफ कर दिया कि प्रदूषण को लेकर औपचारिक लिस्टिंग या प्रतीकात्मक सुनवाई से काम नहीं चलने वाला। अब इस मामले में नियमित और लगातार सुनवाई होगी, ताकि समस्या की तह तक जाकर समाधान के रास्ते खोजे जा सकें। मगर अदालत का यह सख्त स्वर भी इस कड़वे सच को खारिज नहीं करता कि प्रदूषण किसी एक आदेश से खत्म होने वाला संकेत नहीं है। जैसा कि सीजेआई ने कहा-कोई आदेश दें और अगले दिन साफ हवा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस टिप्पणी में पूरे संकेत का सार छिपा है। समस्या सबको पता है, पर समाधान शासन, प्रशासन और वैज्ञानिकों के ठोस कदमों पर निर्भर है। दिल्ली की हवा का हाल इस समय भयावह स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गुरुवार को रजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रहा। यह स्तर सीधे तौर पर ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। इसका अर्थ है कि हवा में मौजूद जहरीले कण शरीर के हर हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पिछले कुछ वर्षों में नवंबर, दिसंबर अब त्योहारों और सड़ियों की शुरुआत का मौसम नहीं रह गया, बल्कि प्रदूषण की चमस स्थिति का संकेत बन चुके हैं। इस बार भी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग घरों के भीतर कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ताजा सर्वे बताते हैं कि लाभग 76 प्रतिशत लोग लगातार घरों में दुकूबे हुए हैं, क्योंकि बाहर निकला जाना अथवा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जैसा महसूस होता है। 80 प्रतिशत नागरिकों को लगातार खांसि, गले में जलन, थकान, सांस में भारीगन और आंखों में चुनचुन जैसी समस्याएँ हो रही हैं। इन दिक्कतों के कारण 69 प्रतिशत लोग कम से कम एक बार डॉक्टर के पास जा चुके हैं। यह स्थिति किसी अस्थायी पेशानी का संकेत नहीं बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य आपदा का चित्रण है। एक ऐसी आवाज जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी

स्वास्थ्य आपातकाल कहकर संबोधित किया है। सबसे गंभीर पहलु यह है कि लोग दिल्ली को छोड़ने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। 80 प्रतिशत लोग मानते हैं कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो उन्हें शहर छोड़ना पड़ सकता है, और 37 प्रतिशत लोग तो रजधानी से बाहर प्रॉपर्टी तलाशना भी शुरू कर चुके हैं। महानगर की अर्थव्यवस्था, रोजगार बाजार और सामाजिक संरचना पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। देश की रजधानी अगर नागरिकों को सुखा नहीं दे पाए, तो यह न केवल प्रशासनिक विफलता है बल्कि भविष्य के शहरी भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है।दिल्ली की खराब हवा केवल सीजेआई ने बुजुर्गों के लिए ही हानिकारक नहीं है। यह आने वाली पीढ़ियों को जन्म से पहले ही अपने दुष्प्रभावों में घेर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, विषैली हवा में लंबे समय तक रहने से नवजात शिशुओं में कई तरह की जन्मजात बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इसका खतरनाक असर पड़ता है।कम वजन वाले बच्चों का जन्म, समय से पहले डिलीवरी और फेफड़ों के विकास में बाधा जैसी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। यह स्थिति उस स्तर की है जहां हवा सिर्फ एक पर्यावरणीय चुनौती नहीं रही, बल्कि यह मानव विकास में बाधा जैसी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। विकास और भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला संकेत बन चुकी है। इन हालातों में नागरिकों का यह मानना स्वाभाविक है कि सरकारें प्रदूषण के खिलाफ ‘राजनीतिक इच्छा शक्ति’ नहीं दिखा रही। कई लोगों की धारणा है कि यह संकेत हर साल दोहराया जाता है, पर कार्रवाई का स्तर हमेशा सीमित और देशी से होता है। चाहे पराली जलने का मामला हो, औद्योगिक धुआं, डीजल वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण स्थलों की धूल या शहरी कचरे का गलत प्रबंधन,हर तरफ कठोर और स्थायी नीति बनाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार इसी निष्क्रियता पर गहरी टिप्पणी थी है।अदालत ने साफ कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही दिल्ली-एन्सीआर की हवा साफ हो जाएगी। एक ऐसी आवाज जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी

पास है, जिन्हें दीर्घकालिक रणनीति बनाकर तुरंत अमल शुरू करना होगा। अदालत की नियमित सुनवाई भले ही इस मामले में जवाबदेही तय करने का एक महत्वपूर्ण मंच बने, पर असली लड़ई जमीन पर ही लड़ी जाएगी।जहाँ कानूनों का सख्ती से पालन, उत्सर्जन पर वास्तविक नियंत्रण और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर निर्णायक कार्रवाई ही कारगर सिद्ध हो सकती है। दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में अभी तक ज्यादातर उपाय अल्पकालिक दिखते रहे हैं।जैसे स्कूल बंद करना, वाहनों पर प्रतिबंध लगाना, निर्माण गतिविधियों को रोकना आदि। लेकिन ये कदम समस्या को केवल कुछ दिनों के लिए कम करते हैं, खत्म नहीं। दीर्घकालिक उपायों पर सरकारें धीमी दिखती हैं। विशेषज्ञ वर्गों से सुझाव दे रहे हैं कि दिल्ली-एन्सीआर को एक साझा हवा प्रबंधन क्षेत्र की तरह चलाया होगा, जहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिलकर नीतियाँ बनाएँ और लागू करें। पराली प्रबंधन, शहरी नियोजन, सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण, हरित क्षेत्रों का विस्तार ये सभी कदम व्यापक और निरंतर प्रयास की मांग करते हैं। यह भी सच है कि नागरिकों का व्यवहार भी इस लड़ई में बखरब की भूमिका निभाता है। निजी वाहनों में अनावश्यक यात्राएँ, पटाखों का अत्यधिक उपयोग, कचरे का खुले में जलना, पेड़-पौधों की उखाड़, ये सब व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें बदलना समय की जरूरत है। हवा को साफ करना केवल सरकारों या अदालतों का दायित्व नहीं, बल्कि यह 2 करोड़ से अधिक लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। पर व्यक्तिगत प्रयास तभी प्रभावी होंगे जब सरकारें बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएँ और प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। आज अदालत का सख्त रुख दिल्ली वालों में उम्मीद जगाता है कि शायद अब इस समस्या को गहरी टिप्पणी भी है।अदालत ने साफ कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही दिल्ली-एन्सीआर की हवा साफ हो जाएगी। एक ऐसी आवाज जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी



बदल सकता है। लेकिन यह भी समझना होगा कि समाधान वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों की सलाह से ही निकलेंगे और उन पर अमल तभी होगा जब राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत होगी। दिल्ली की हवा का संकेत केवल एक मौसम की समस्या नहीं है। यह देश की रजधानी की प्रतिष्ठ, जनता के स्वास्थ्य, बच्चों के भविष्य और शहर की आर्थिक समृद्धि का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और सख्त टिप्पणी एक प्रकार से अंतिम संकेत है कि अब समय हाथ से निकलता जा रहा है। अब यह कहना पर्याप्त नहीं कि प्रदूषण एक जटिल समस्या है। बल्कि अब जरूरत है कि इसे खत्म करने के लिए जटिल लेकिन आवश्यक कदम उठाए जाएँ। और ये कदम तभी जमीन पर असर दिखाएंगे जब सरकारें वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दीर्घकालीन नीति बनाएँ, और उसे बिना किसी राजनीतिक दबाव या वोट बैंक की चिंता के लागू करें। दिल्ली की सांसों की यह लड़ई अब अदालत की गिराणी में नहीं। लेकिन असली जीत तब होगी जब रजधानी के नागरिक रोज सुबह उठकर यह महसूस कर सकें कि हवा में जहर नहीं, जीवन है। जब बच्चे बिना मास्क के स्कूल जा सकें, जब बुजुर्ग बिना डर के सैर कर सकें, और जब अस्पतालों की भीड़ कम होकर सामान्य हो जाए। यह सपना संभव है, लेकिन तभी जब इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक समझ, राजनीतिक दृढ़ता और सामाजिक जिम्मेदारी सभी मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आगाह किया है, अब बारी शासन की है कि वह साबित करे कि वह हवा को साफ करना चाहता भी है और कर भी सकता है।

कांतिलाल मांडेठ

जब खुद के घर में आग लगती है तभी धुएं का एहसास होता है

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डी.सी. में राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति निवास की सुरक्षा में तैनात नेशनल गार्ड पर एक अफगानी नागरिक द्वारा फायरिंग किए जाने से एक गार्ड की मृत्यु हो जाती है और एक गाड़ की गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अमेरिका प्रशासन ने इस घटना को अपनी अस्मिता पर हमला मानते हुए इसे आतंकी हमला करार देते हुए समूचे अमेरिका में वैध- अवैध रूप से रह रहे लाखों अफगानियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बेशक अमेरिका में हुआ हमला पुलवामा या पहलगाम के आतंकी हमले की तरह न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत भयावह, लेकिन फिर भी अच्छी और सीखने लायक बात यह है कि अमेरिका प्रशासन की राष्ट्र फर्स्ट नीति के तहत हमला छोटा या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। अमेरिका प्रशासन के लिए पूरे अमेरिका में एक भी गोली किसी गैर-अमेरिकी द्वारा चलाया जाना राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा मायने रखता है, और अमेरिकी सेना, खुफिया एजेंसियां और प्रशासन गोली चलाने वाले के साथ-साथ उससे संबंधित मुल्क को भी राष्ट्र की अस्मिता पर हमला करने वाला दोषी मानते हैं और समूचे मुल्क

को अमेरिका की नीतियों का कोप झेलना पड़ता है। अमेरिका पर नेशनल गार्ड पर फायरिंग करने वाला अफगानी कोई आतंकी नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का सहयोग करने वाला अफगानी ही था। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस अमेरिका आने के साथ करीब पचास हजार से ज्यादा अफगानी भी अपनी जान बचाकर अमेरिका आ गए थे, और अमेरिका में नागरिकता नहीं मिलने के कारण तथा ट्रम्प प्रशासन के अड़ियल रवैये के चलते सेना के साथ आए अफगानियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वाशिंगटन डी.सी. में हुए नेशनल गार्ड पर फायरिंग की घटना इसी बात का प्रतीक थी, लेकिन अमेरिका ने इस छोटे से हमले को भी राष्ट्र की अस्मिता पर हमला मानते हुए इसे आतंकी हमला करार देकर अब अमेरिका में रह रहे लाखों अफगानियों के सामने जीवन-मरण की स्थिति पैदा कर दी है। बकौल अमेरिका, अपने ऊपर आतंकी हमले करने वाले अफगान-यादव और उनके आकाओं को खत्म कर आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की हालत खराब कर दी हो, लेकिन फिर भी अमेरिका की आतंकवाद पर कभी एक वैश्विक नीति नहीं रही है। अमेरिका की

आतंकवाद पर अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग नीति है। इसी वजह से आतंकवाद फिर फन फैला रहा है। दुनिया की महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका अपने ऊपर हुए एक छोटे से हमले को भी बड़ा आतंकी हमला मानकर उसकी तह में जाकर खोज कर रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा आतंकी मकसद तो नहीं है। यानी जब खुद के घर में आग लगती है तभी धुएं का एहसास होता है। और जब भारत जैसे देशों में आतंक की बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं तो यही अमेरिका आतंकवाद का फन कुचलने की बजाय आतंक के आकाओं की अपने घर में अगवानी करके बिरयानी खिलाते नजर आता है।

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित समूचे अमेरिका के लिए यह छोटी-सी फायरिंग की आतंकी घटना एक बड़ा संदेश देती है कि यदि आप अपने व्यापारिक हितों के लिए विश्व के देशों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए अपने हथियारों के बल पर आतंकियों देशों के सहारे कमजोर करने की नियत रखोगे, तो यही पाले हुए आस्तीन के सांप आपको भी उतना ही डसेंगे जितना दूसरों को डसते हैं। अतः डोनाल्ड ट्रम्प को अपने व्यापारिक हितों के



साथ-साथ अमेरिका को और दुनिया के देशों को आतंकवाद से सुरक्षा देने के लिए एक समान नीति रखनी होगी। और महाशक्ति होने के नाते समस्त विश्व का नेतृत्व करते हुए दुनिया के कोने-कोने में छुपे बैठे आतंकियों के समूल नाश का संकल्प लेना होगा। तभी दुनिया से आतंकवाद खत्म होगा, अन्यथा किसी दिन भी अमेरिका के न्यूयॉर्क या लॉस एंजेलिस से पुलवामा या पहलगाम से बड़ी आतंकी घटना होगी और तब उसकी चीखों से अमेरिका को सही मायनों में आतंक के दर्द और धुएं की भयावहता का एहसास होगा।

अरविंद रावल

महिला प्रीमियर लीग में दीया यादव के चयन से बदला खेल का नजरिया

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का मेगा ऑक्शन इस बार केवल नीलामी का मंच नहीं था, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट में बदलते समय और बदलती सोच का प्रतीक बनकर उभरा। 16 वर्षीय दीया यादव का चयन केवल एक साहसिक कदम नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी के उदय का संकेत है। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें मात्र 10 लाख रुपये के बेस प्राइस पर चुनकर दिखा दिया कि प्रतिभा की पहचान उम्र से नहीं, साहस और निरंतरता से होती है। दीया के चयन ने महिला क्रिकेट में वही हलचल पैदा की है, जैसी कभी आईपीएल में 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू ने की थी। दोनों घटनाएँ न सिर्फ खेल की दिशा बदलने वाली हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि भारतीय क्रिकेट अब युवाओं के लिए पहले से कहीं अधिक स्वागतशील मंच बन चुका है। दीया यादव का उदय अचानक से नहीं हुआ। उनका नाम भले ही अभी सुर्खियों में आया हो, लेकिन उनकी यात्रा लंबे समय की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष की कहानी है। 2023 की अंडर-15 महिला वनडे ट्रांफी से उन्होंने जिस विस्फोटक अंदाज में अपने करियर की घोषणा की, वह किसी भी उमरते खिलाड़ी की लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। 96.33 की औसत और 578 रन अपने आप में अद्भुत उपलब्धि हैं, लेकिन तीन शतक और एक दुर्लभ डबल सेंचुरी दर्शाती हैं कि यह लड़की केवल प्रतिभाशाली नहीं है—वह मानसिक रूप से भी अत्यंत मजबूत है। नबाब 124 रनों की पारी के बाद जिस

तरह वह दिल्ली की चर्चाओं में आई, वह साफ दर्शाता है कि घरेलू क्रिकेट का दायरा अब उन प्रतिभाओं को पहचानने लगा है, जिन्हें पहले अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। हरियाणा जैसी धरती, जहाँ पहले से ही कई बड़े खिलाड़ी जन्म ले चुके हैं, वहाँ दीया का उभरना आश्चर्य नहीं, बल्कि परंपरा का विस्तार है। लेकिन इसे अलग पहचान इसलिए मिलती है क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही जिस परिपक्वता के संकेत दिए, वह बड़े स्तर पर सफलता की मजबूत संभावना दिखाते हैं। 2025-26 के सत्र में सीनियर टीम के लिए नंबर तीन पर खेलते हुए शेफाली वर्मा के साथ उनकी जोड़ी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सिर्फ प्रतिभा तक सीमित नहीं, बल्कि टीम के संतुलन और रणनीति का भी हिस्सा बन सकती हैं। यह साझेदारी केवल दो बल्लेबाजों का मिलन नहीं, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की नई मानसिकता का प्रतीक बन गई—तेज, निडर और बेझिझक क्रिकेट खेलने का मानसिकता। टी20 प्रारूप स्वाभाव से चुनौतीपूर्ण है। तेज निर्णय, निरंतर जोखिम और सीमित अवसर—इन तीनों का संतुलन ही इस प्रारूप की असली परीक्षा होती है। इस परीक्षा में दीया यादव ने जिस सहजता से सफलता हासिल की है, वह बताता है कि वह भविष्य की नहीं, वर्तमान की खिलाड़ी हैं। नॉर्थ जोन के लिए इंटर-जोनल टी20 ट्रांफी में लगभग 150 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाना, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट की सूची में ऊपर रहना और संभव अधिक चौके लगाने वालों में

दूसरा स्थान पाना—ये उपलब्धियाँ बताती हैं कि उन्होंने टी20 मानसिकता को बखूबी समझ लिया है। उनका टी20 करियर भी यही कहानी कहता है—19 पारियों में लगभग 40 की औसत पर 590 रन और चार अर्धशतक दिखाते हैं कि वे स्थिरता और आक्रामकता दोनों का संतुलन बनाए रख सकती हैं। सीनियर टी20 ट्रांफी में लगभग 60 की औसत के साथ 298 रन बनाकर उन्होंने न केवल नॉर्थ जोन को फाइनल तक पहुँचाया, बल्कि चयनकर्ताओं का भरोसा भी मजबूत किया कि वह कठिन परिस्थितियों में भी टिक सकती हैं। दिल्ली कैपिटल्स का उन पर भरोसा केवल एक टीम की रणनीति नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की बड़े बदलावों का संकेत है। अब टीमों जोखिम लेने से नहीं डरतीं। वे उस प्रतिभा को तराशने का जोखिम उठाती हैं, जो आने वाले वर्षों में टीम का भविष्य बदल सकती है। लॉरा वॉल्फर्ट और स्टेन राणा जैसी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ एक 16 वर्षीय उमरती प्रतिभा को जगह देना बताता है कि दिल्ली की टीम अनुभव और युवा निर्णय, निरंतर जोखिम और सीमित अवसर—इन तीनों का संतुलन ही इस प्रारूप की असली परीक्षा होती है। इस परीक्षा में दीया यादव ने जिस सहजता से सफलता हासिल की है, वह बताता है कि वह भविष्य की नहीं, वर्तमान की खिलाड़ी हैं। नॉर्थ जोन के लिए इंटर-जोनल टी20 ट्रांफी में लगभग 150 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाना, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट की सूची में ऊपर रहना और संभव अधिक चौके लगाने वालों में



की सीमाओं में बॉधकर रख देती हैं। उनका उभरना उन परिवारों के लिए भी संदेश है जो अब अपनी बेटियों को खेल के मैदान तक पहुँचाने में हिचकिचाते नहीं। टेंड बल्लर रहा है—और इस बदलाव में दीया यादव जैसी खिलाड़ी अग्रदूत हैं। भारतीय महिला क्रिकेट आज जिस ऊर्चाई पर खड़ा है, वहीं ऐसे साहसी कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले समय में यह और भी सशक्त होगा। दीया का चयन महज एक खबर नहीं, बल्कि एक घोषणा है—कि भारतीय महिला क्रिकेट का भविष्य सुनिश्चित हाथों में है। यदि वह अपने उसी जोश और दृढ़ता को बनाए रखती हैं जिसका प्रदर्शन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में किया है, तो वह आने वाले वर्षों में भारतीय टीम की मुख्य स्तंभ बन सकती हैं। डुक्क उनके लिए केवल एक मंच नहीं, बल्कि वह दरवाजा है जहाँ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुँचने का रास्ता खुलता है। वह रास्ता लंबा है, चुनौतियों से भरा है, परंतु उनके शुरुआती सफर ने बता दिया है कि वह इस यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

महेन्द्र तिवारी

संपादकीय

वेद-उपनिषदों के आलोक में प्रदीप्त होता वैश्विक आकाश

अयोध्या से विश्वशांति का नवोदय।

वेद, उपनिषद और पुराणों का ज्ञान भारतीय चेतना का वह दिव्य आलोक है जिसने सहस्राब्दियों से संपूर्ण मानवता को दिशा दी है। इन प्राचीन ग्रंथों में निहित ऊर्जा, तत्वज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति केवल धर्मग्रंथ नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के प्रकाशस्तंभ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्र केवल ध्वनियाँ नहीं, बल्कि जीवन का अनंत संगीत हैं जो मनुष्य को बाह्य नहीं, अंतरंग रूप से परिष्कृत करते हैं और यह बताते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियों नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार है। आज जब संपूर्ण विश्व लिए जटिल लेकिन आवश्यक कदम उठाए जाएँ, और ये कदम तभी जमीन पर असर दिखाएंगे जब सरकारें वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दीर्घकालीन नीति बनाएँ, और उसे बिना किसी राजनीतिक दबाव या वोट बैंक की चिंता के लागू करें। दिल्ली की सांसों की यह लड़ई अब अदालत की गिराणी में नहीं। लेकिन असली जीत तब होगी जब रजधानी के नागरिक रोज सुबह उठकर यह महसूस कर सकें कि हवा में जहर नहीं, जीवन है। जब बच्चे बिना मास्क के स्कूल जा सकें, जब बुजुर्ग बिना डर के सैर कर सकें, और जब अस्पतालों की भीड़ कम होकर सामान्य हो जाए। यह सपना संभव है, लेकिन तभी जब इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक समझ, राजनीतिक दृढ़ता और सामाजिक जिम्मेदारी सभी मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आगाह किया है, अब बारी शासन की है कि वह साबित करे कि वह हवा को साफ करना चाहता भी है और कर भी सकता है।



में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में निहित है। यह विचार आज विश्व के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विमर्शों का आधार बन रहा है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि वैश्विक नेतृत्व का बड़ा भौतिक उपलब्धियों नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार है। आज जब संपूर्ण विश्व लिए जटिल लेकिन आवश्यक कदम उठाए जाएँ, और ये कदम तभी जमीन पर असर दिखाएंगे जब सरकारें वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दीर्घकालीन नीति बनाएँ, और उसे बिना किसी राजनीतिक दबाव या वोट बैंक की चिंता के लागू करें। दिल्ली की सांसों की यह लड़ई अब अदालत की गिराणी में नहीं। लेकिन असली जीत तब होगी जब रजधानी के नागरिक रोज सुबह उठकर यह महसूस कर सकें कि हवा में जहर नहीं, जीवन है। जब बच्चे बिना मास्क के स्कूल जा सकें, जब बुजुर्ग बिना डर के सैर कर सकें, और जब अस्पतालों की भीड़ कम होकर सामान्य हो जाए। यह सपना संभव है, लेकिन तभी जब इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक समझ, राजनीतिक दृढ़ता और सामाजिक जिम्मेदारी सभी मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आगाह किया है, अब बारी शासन की है कि वह साबित करे कि वह हवा को साफ करना चाहता भी है और कर भी सकता है।

जब उसमें सामुदायिक श्रम, सामाजिक उपयोगिता और आत्मिक संतोष का सम्मिलन हो। यही वह सिद्धांत है जिसने राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को समाज की कुरीतियों और जड़ता के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति दी। यही वह ऊर्जा है जिसने सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन खड़ा करने की प्रेरणा दी, कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों के लिए विश्व- अभियान चलाने का साहस दिया, और बिल गेट्स तथा बॉरन बफेट को अपनी अकृत संपत्ति का विशाल भाग मानव सेवा में लगाने का संकल्प दिया। एडिसन, आईस्टीन, मैडम क्यूरी और राइट बंधु सफलता के पीछे नहीं भागे, उन्होंने सार्थकता को उद्देश्य बनाया। यदि वे केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित रहते, तो उनके आविष्कार मानवता की धरोहर न बन पाते।सफलता क्षणिक सुख दे सकती है, पर सार्थक श्रम ही वह दीप है जो जीवन को स्थायी उजाला देता है और समाज को पथप्रदर्शक। जब श्रम, परिश्रम और प्रयत्न एक साथ मिलते हैं, तभी चिरस्थायी आनंद, आत्मिक संतोष और मानवता की उन्नति संभव होती है। यही वेदों की परंपरा का सार है और यही अयोध्या के ध्वजारोहण का संदेश पहले अशांति को परास्त करो, तभी शांति का ध्वज फहराएगा। आज भारत विश्व को बता रहा है कि युद्ध का अंत हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों और संस्कृति की शक्ति से होता है। अयोध्या का शांतिमय ध्वज अब केवल भारत का प्रतीक नहीं, बल्कि विश्व मानवता की दिशा है। भारत निरंतर वैश्विक शिक्षक की ओर बढ़ रहा है और यह प्रस्थान मार्ग शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों की रोशनी से आलोकित है। यही है नया युग विश्वशांति का, वैश्विक एकता का और भारतीय नेतृत्व का।

संजीव ठाकुर

बहुपत्नीत्व अब इतिहास—असम ने बदल दी सदियों की परंपरा

[समान अधिकार का बिगुल— असम ने देश को नई दिशा दी] [असम का बड़ा फैसला: महिला सम्मान अब कानून की ढाल] 27 नवंबर 2025 का दिन असम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी दिन विधानसभा ने भारी बहुमत से ‘असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल-2025’ पारित कर वह कदम उठाया, जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। इस कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी करेगा तो उसे सात वर्ष का कारावास भुगताना होगा, और यदि यह शादी छिपाकर की गई है तो सजा बढ़कर दस वर्ष तक पहुँच जाएगी, साथ ही अलग से भारी जुर्माना भी देना होगा। दंड केवल जेल और जुर्माने तक सीमित नहीं है—दोषी को जीवनभर किसी भी सरकारी नौकरी, चाहे वह चपरासी स्तर की हो या आईएएस जैसी उच्च सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही, पंचायत से लेकर नगर निगम तक किसी भी पद का सभा कल्याणकारी योजनाएँ, पेंशन तथा राशन सुविधाएँ भी तुरंत बंद हो जाएँगी। इतना ही नहीं, यदि कोई जैसी खिलाड़ी अग्रदूत हैं। भारतीय महिला क्रिकेट आज जिस ऊर्चाई पर खड़ा है, वहीं ऐसे साहसी कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले समय में यह और भी सशक्त होगा। दीया का चयन महज एक खबर नहीं, बल्कि एक घोषणा है—कि भारतीय महिला क्रिकेट का भविष्य सुनिश्चित हाथों में है। यदि वह अपने उसी जोश और दृढ़ता को बनाए रखती हैं जिसका प्रदर्शन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में किया है, तो वह आने वाले वर्षों में भारतीय टीम की मुख्य स्तंभ बन सकती हैं। डुक्क उनके लिए केवल एक मंच नहीं, बल्कि वह दरवाजा है जहाँ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुँचने का रास्ता खुलता है। वह रास्ता लंबा है, चुनौतियों से भरा है, परंतु उनके शुरुआती सफर ने बता दिया है कि वह इस यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

मुस्लिम देशों में पॉलीगैमी पहले से प्रतिबंधित है, और पाकिस्तान में भी दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी की लिखित अनुमति जरूरी है। असम ने केवल न्याय और सच्चे धर्म का साथ दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यही युनिफॉर्म सिविल कोड की पहली सीढ़ी है, और 2026 में सरकार दोबारा बनी तो पूरा यूसीसी लागू किया जाएगा। सच यह है कि बहुपत्नीत्व कभी किसी का ‘धार्मिक अधिकार’ नहीं था, यह हमेशा पुरुष की सुविधा और स्त्री की मजबूरी का हथियार रहा। पहली पत्नी को भावनाओं सहित कैद कर देना, उनके बच्चों को आर्थिक-मानसिक रूप से तोड़कर दूसरी-तीसरी शादी रचाना—क्या यही मर्दानगी है? एनएफएचएस-5 बताता है कि पूर्वोत्तर के हजारों परिवार आज भी इसी जहर से धीमे-धीमे टूट रहे हैं। पहली पत्नी के पास न तलाक का अधिकार बचता, न गुजारा भत्ता, न वारिस में बराबरी; बच्चे नई शादियों की दहलीज पर ही पिस जाते हैं। असम ने निर्णायक निर्णय लिया—अब बस। अब औरत का हक, किसी भी धर्म की आड़ से ऊपर रखा जाएगा। यह कानून केवल सजा का हथियार नहीं, समाज को नई नींव देने वाला क्रांतिकारी दस्तावेज है। पीड़ित महिला को तुरंत मुआवजा, मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी सुरक्षा कवच मिलेगा। पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होगा, जबकि दोबारा अपराध करने वाले को दोगुनी—यानी बीस वर्ष तक—की कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। ये का दंड तय है। यह कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख—सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा, हाँ, छठी अनुसूची के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी स्थानीय परिषदों के माध्यम से इस प्रकार का समान कानून लागू करने का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने विधानसभा में कहा, ‘यह बिल किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन कुरीतियों के खिलाफ है जिन्होंने सदियों से औरत को बंधन में रखा है। तुर्की, ट्यूनीशिया जैसे कई

उत्तर प्रदेश—सबकी सरकारें अब जनता के तीखे सवालों का सामना करेंगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में, जहां एनएफएचएस डेटा आज भी 2 - 3% पॉलीगैमी दिखाता है, उन्हें जवाब देना युनिफॉर्म सिविल कोड की पहली सीढ़ी है, और 2026 में सरकार दोबारा बनी तो पूरा यूसीसी लागू किया जाएगा। सच यह है कि बहुपत्नीत्व कभी किसी का ‘धार्मिक अधिकार’ नहीं था, यह हमेशा पुरुष की सुविधा और स्त्री की मजबूरी का हथियार रहा। पहली पत्नी को भावनाओं सहित कैद कर देना, उनके बच्चों को आर्थिक-मानसिक रूप से तोड़कर दूसरी-तीसरी शादी रचाना—क्या यही मर्दानगी है? एनएफएचएस-5 बताता है कि पूर्वोत्तर के हजारों परिवार आज भी इसी जहर से धीमे-धीमे टूट रहे हैं। पहली पत्नी के पास न तलाक का अधिकार बचता, न गुजारा भत्ता, न वारिस में बराबरी; बच्चे नई शादियों की दहलीज पर ही पिस जाते हैं। असम ने निर्णायक निर्णय लिया—अब बस। अब औरत का हक, किसी भी धर्म की आड़ से ऊपर रखा जाएगा। यह कानून केवल सजा का हथियार नहीं, समाज को नई नींव देने वाला क्रांतिकारी दस्तावेज है। पीड़ित महिला को तुरंत मुआवजा, मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी सुरक्षा कवच मिलेगा। पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होगा, जबकि दोबारा अपराध करने वाले को दोगुनी—यानी बीस वर्ष तक—की कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। ये का दंड तय है। यह कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख—सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा, हाँ, छठी अनुसूची के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी स्थानीय परिषदों के माध्यम से इस प्रकार का समान कानून लागू करने का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने विधानसभा में कहा, ‘यह बिल किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन कुरीतियों के खिलाफ है जिन्होंने सदियों से औरत को बंधन में रखा है। तुर्की, ट्यूनीशिया जैसे कई

प्रो. आरके जैन



संक्षिप्त खबरें

महिला शिक्षा के प्रणेता थे ज्योतिबा फुले – चंद्रभूषण देवरिया। महात्मा ज्योतिबा फुले के स्मृति दिवस पर सपा के पूर्व प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह यादव ने कहा कि फुले साहब ने महिला शिक्षा को सामाजिक बदलाव का आधार मानते हुए देश का पहला कन्या विद्यालय शुरू कर इतिहास बनाया। सावित्रीबाई फुले के साथ उनकी पहल ने शिक्षा को बंचितों तक पहुंचाने का नया रास्ता खोला। उन्होंने बताया कि फुले ने 1848 में कन्या विद्यालय और 1855 में श्रमिकों व किसानों के लिए सायंकालीन विद्यालय शुरू किया। जाति उन्नीड़न के खिलाफ उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर सामाजिक समता का मजबूत आंदोलन खड़ा किया। 1890 में निधन के बावजूद उनका योगदान आज भी समाज सुधार का मार्गदर्शन करता है। कार्यक्रम में सुरेश नारायण सिंह, गोविंद यादव, नाशिर अंसारी सहित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

नगर पालिका अध्यक्ष ने पी.एम. श्री विद्यालय नं. 1 में जमा कराए एस आई आर फॉर्म



शुद्ध पेयजल हेतु लगाया गया स्टैंड पोस्ट

बरहज,देवरिया। पी.एम. श्री विद्यालय संख्या 1 पर नगर पालिका अध्यक्ष खेता जायसवाल एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि श्यामसुंदर जायसवाल पहुंचे, जहां उन्होंने एस आई आर से संबंधित फॉर्म बीएलओ के पास जमा किए। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। विद्यालय के छात्रों, छात्राओं एवं प्रधानाध्यापक की मांग पर नगर पालिका द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्टैंड पोस्ट लगाया गया है। स्टैंड पोस्ट के आसपास टाइल्स लगाने का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है, ताकि बच्चों को स्वच्छ और सुविधाजनक पेयजल व्यवस्था मिल सके। नगर पालिका द्वारा एस आई आर फॉर्म के कार्य को शीघ्रता से पूरा कराने के लिए अपने कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। विद्यालय में आए मतदाताओं को अध्यक्ष ने एस आई आर फॉर्म समय से भरकर जमा करने के लिए प्रेरित किया और आवश्यक जानकारी देकर जागरूक किया। नगर पालिका प्रशासन ने कहा कि छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है, और इस दिशा में ठोस कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।

मार्ग से अतिक्रमण हटवाने को लेकर दो तहरीर

लालगंज, प्रतापगढ़। मार्ग में अतिक्रमण के आरोप को लेकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। लालगंज कोतवाली के बधनपुर अवदर गांव निवासी दुर्गा प्रसाद तिवारी पुत्र श्रीकांत तिवारी ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा गांव में आने जाने के खडपजा मार्ग पर अतिक्रमण कर मार्ग को अवरूद्ध कर दिया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि आगामी उत्तीस नवंबर को बेटी की बारात आनी है। मार्ग से अतिक्रमण हटाने की बात करने पर आरोपी मारपीट पर आमदा हो जाता हो जाता है। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जायेगी।

अज्ञात चालक पर गैरइरादतन हत्या का केस

लालगंज, प्रतापगढ़। दुर्घटना में युवक की हुई मौत को लेकर पुलिस ने अज्ञात बोलरो चालक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। लालगंज कोतवाली के मोठिन गांव निवासी पृथ्वी पाल पुत्र सियम्बर ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि बीती 23 नवंबर की शाम करीब 6.30 बजे उसके पिता खेत से घर लौट रहे थे। प्राथमिक विज्ञापन मोठिन के पास अज्ञात बोलरो वाहन ने टक्कर मार दिया। जिससे पीड़ित के पिता सियम्बर की मौत हो गयी थी। जांच के निष्पत्ति आलोक कुमार का कहना है कि जांच के बाद अज्ञात बोलरो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

शीतलहर से बचाव हेतु जनपद में एडवाइजरी जारी

देवरिया।एडीएम वित्त एवं राजस्व रामशंकर ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा शीतलहर की संभावना के मद्देनजर जनपद में सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।आश्रय स्थलों, अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कंबल, दवाई, हीटर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। रैन बसेरों की विशेष समीक्षा, फिसलन वाले स्थानों पर नमक/रेत का छिड़कवाव तथा कोहरे में सड़क सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मृत बीएलओ अंजू के परिजनों से की मुलाकात

लेखपालों के धरने को दिया समर्थन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रुद्रपुर-देवरिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय प्रवक्ता रुद्रपुर विधानसभा के पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह के साथ शुक्रवार को माझा निवासी की बीएलओ अंजू देवी के परिजनों से मुलाकात की व उन्हें सांत्वना दी। वहां से लौटने के बाद दोनों नेताओं ने तहसील परिसर में चल रहे लेखपालों के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शिरकत की व उनका समर्थन भी किया।स्थानीय तहसील परिसर में फतेहपुर जिले के 2024 बैच के लेखपाल सुधीर कुमार द्वारा आत्महत्या कर लेने और शासन प्रशासन द्वारा इसको दबाने व फिर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करने को लेकर लेखपालों में भारी आक्रोश देखा गया। जिससे आहत होकर तहसील लेखपाल संघ के अध्यक्ष देवेन्द्र त्रिपाठी और मंत्री भास्कर के नेतृत्व में एकदिवसीय धरना



प्रदर्शन किया गया। इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने धरना स्थल पर पहुंच कर धरने को संबोधित करते हुए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। उन्होंने मांग किया कि लेखपाल सुधीर कुमार के परिवार को एक करोड़ रुपए और उनकी अकेली बहन को सरकारी नौकरी दी जाय।

प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार द्वारा समर्थित और चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश भर में किये जा रहे हैं एस आई आर (स्पेशल इंस्टिच रिवीजन) पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया। इससे आम जनता में भारी नाराजगी और

रविन्द्र किशोर शाही स्टेडियम में खेलो इंडिया अस्मिता एथलेटिक्स बालिका लीग सम्मन, डीएम ने बढ़ाया उत्साह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

देवरिया। रविन्द्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम, देवरिया में खेलो इंडिया अस्मिता एथलेटिक्स बालिका लीग का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर विभिन्न एथलेटिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहीं बालिकाओं का हौसला बढ़ाया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बालिकाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने हेतु मंच उपलब्ध कराना है। स्पिंट, लंबी कूद, ऊँची कूद सहित कई इवेंट भी किया जाएगा। कृषि एवं सहयोगी विभाग, यूपी एगो, बीज निगम और कृषि यंत्र निर्माता कंपनियाँ भी स्टील लगाएंगी। कृषि ऋण शिविर भी आयोजित होगा।

अफरा-तफरी का माहौल है। सन 2002 में एस आई आर की प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसमें कुल 8 महीनों का समय दिया गया था। जिससे एस आई आर प्रक्रिया करने में कोई बाधा नहीं आई थी, किंतु इस गूंगी बहरी सरकार में एक महीने से कम समय दिया गया है। जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बन रहा है। मानसिक दबाव की वजह से कई कर्मचारी आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरलीकरण हो और इसकी समय सीमा बड़ाई जाए ताकि जो कर्मचारी इसमें लगे हैं बिना किसी दबाव के निर्वाह रूप से अपन कार्य पूरा कर सकें। इस अवसर पर शिव शंकर गुप्ता, नागेंद्र बहादुर रत्न, रागिनी सिंह, मयंक गुप्ता, लक्ष्मी चौधरी, मनीष गुप्ता, नीरज मुनी, सिद्धार्थ गौतम, अजय यादव, सचिन सिंह, वृजेश शुक्ला आदि लेखपाल और कर्मचारी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने बालगृह के बच्चों को दिए गर्म जैकेट



देवरिया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शीतलहर से बचाव हेतु बालगृह में बच्चों को गर्म जैकेट वितरित किए। इस दौरान उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद किया और उन्हें जैकेट पहनकर उत्साहित किया। डीएम ने बालगृह की आवासीय व देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर अधिकारियों को बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित व खुशहाल वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। जैकेट वितरण से बच्चों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में सीएमओ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, एसीएमओ डॉ. अश्वनी कुमार पांडेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

फतेहपुर के लेखपाल की मौत पर कार्रवाई की मांग तेज, गोरखपुर में लेखपालों का धरना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिला इकाई व तहसील सदर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को तहसील सदर परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन हुआ। फतेहपुर के 2024 बैच के लेखपाल सुधीर कुमार की मौत को लेकर लेखपालों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। वक्ताओं ने इसे प्रशासनिक दबाव, संवादहीनता और अधिकारियों की असवेदनशीलता के कारण हुई 'अप्राकृतिक मृत्यु' बताया। और अनुशासन विकसित करते हैं, जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने आवश्यक किया कि प्रशासन जिले की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों, खेल अधिकारियों और अभिभावकों ने भी बालिकाओं के उत्साह व प्रदर्शन की सराहना की।

भूतपूर्व विधायक के प्रतिमा का हुआ अनावरण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवां के रतनपुर ब्लाक मुख्यालय परिसर में शुक्रवार को भूतपूर्व एवं प्रथम विधायक तथा स्वतंत्रता सग्राम सेनानी सुदामा प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण स्वर्गीय सुदामा प्रसाद की पुत्री बीना देवी व पौत्र सुदामा प्रसाद जन कल्याण फाउंडेशन संस्था के संस्थापक प्रभात कुमार सेनानी सुदामा प्रसाद का जन्म 9 मई सन् 1908 को नौतनवां ब्लाक के ग्राम पंचायत रतनपुर में पैदा हुए थे। सुदामा प्रसाद सोलह साल की उम्र में पहली बार जेल गए थे। सुदामा प्रसाद ने भारत से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक क्रांतिकारी कदम उठाकर जगह-जगह संगठन बनाकर अंग्रेज से लड़ कर उन्हें भारत से निकालने का काम किया। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अपने जीवन में



लगभग सत्रह बार जेल गए। जेल में ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। जेल जाने के बाद भी उनका मनोबल गिरा नहीं। देश आजाद होने के बाद लक्ष्मीपुर नौतनवां विधानसभा के प्रथम विधायक हुए। अपने विधायक के कार्यकाल में नौतनवां ब्लाक, सीएचसी रतनपुर, नौतनवां-दूरीबारी मुख्य मार्ग, नौतनवां इंटर कॉलेज, रोहिन हेड का निर्माण कार्य कराया। भूत पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता सग्राम सेनानी सुदामा प्रसाद का 6 अप्रैल 1968 को उनके आवास पर ही देहांत हो गया। इस दौरान सतीश उर्फ बेचन, बाबूलाल यादव, प्रेम नारायण शर्मा, नंद किशोर यादव, कपू मिश्रा, राजू साहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।



उठा लिया। आरोप लगाया गया कि परिजनों के प्रार्थना पत्र के बावजूद 30 घंटे तक FIR दर्ज नहीं हुई और बाद में तहरीर बदलवाकर एक PCS अधिकारी का नाम हटवा दिया गया। धरने में प्रदेश उपाध्यक्ष धनंजय कुमार श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद, तहसील मंत्री रत्नेश सिंह सहित बड़ी संख्या में लेखपाल मौजूद रहे। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि लेखपाल केवल अपने निर्धारित दायित्वों तक सीमित रहें और अनावश्यक अतिरिक्त कार्यों से बचें, ताकि विभाग पर

अनावश्यक दबाव न बढ़े। मुख्यमंत्री संजय कुमार सबसेना को नामजद करने, मृतक परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को नौकरी, SIR की अंतिम तिथि बढ़ाने तथा चुनावी ड्यूटी पर एक माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई। एसडीएम की अनुपस्थिति में जापन नायब तहसीलदार अरविंद नाथ पांडेय को सौंपा गया। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।

बीएलओ रंजू दुबे की मौत पर सपा नेताओं ने जताया शोक, परिजनों से मिले

चुनाव आयोग से मुआवजा व नौकरी की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रुद्रपुर। सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम व पोस्ट माझा नारायन पहुँचा, जहाँ उन्होंने ड्यूटी के दौरान निधन हुई बीएलओ रंजू दुबे के पति जगदम्भा दुबे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सपा परिवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं दुबे परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिना समुचित तैयारी और बेहद कम समय में लागू किए गए एस आई आर कार्य के कारण बीएलओ व बीएलए गंभीर तनाव में हैं, जबकि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में लगन व खेती का कार्य भी चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने अत्यधिक



संवेदनशील एवं बोझिल जिम्मेदारियाँ कर्मचारियों पर थोप दी हैं, जो जानलेवा साबित हो रही हैं। सपा जिलाध्यक्ष ने मांग किया कि मृत बीएलओ के परिवार को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान जाए तथा अतिरिक्त कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाए। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, विजय प्रताप यादव, हाफिज शहादत हुसैन, अली आजम, हरेन्द्र सिंह त्यागी, संतोष यादव, हसनाथ यादव, रामखेटू यादव, सिकंदर यादव, राजनाथ यादव, आदिल, नौशाद, दानिश शेख, विनोद आदि मौजूद रहे।

गोला तहसील की 9 राइस मिलों में धान कुटाई त्प, सरकारी खरीद पर संकट के बादल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोला तहसील क्षेत्र की नौ राइस मिलों में धान की कुटाई का कार्य इस बार शुरू ही नहीं हो सका है। कुटाई न होने से मिलों में धान की आनेक रुकी है और फिलहाल खरीदा गया पूरा धान गोदामों में ही पड़ा है। मिल संचालकों का कहना है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो सरकारी खरीद प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खाद्य विभाग की ओर से इस सीजन में गोला क्षेत्र के चार क्रय केंद्रों पर लगभग 4419 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। वहीं पीसीयू के दो और खरीदारी जारी है, लेकिन राइस मिलों में कुटाई शुरू न होने से खरीदा गया कोई भी



धान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में खरीद कार्य बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। पूर्वांचल राइस मिल एसोसिएशन के गोरखपुर मंडल अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि राइस मिलों पर कुटाई शुरू न होने का मुख्य कारण फोर्टिफाइड चावल की उपलब्धता में देरी है। सरकार के निर्देशानुसार मिलरों को कुटाई के बाद तैयार चावल में एक प्रतिशत फोर्टिफाइड चावल मिलाना अनिवार्य है। जब तक यह मिश्रण नहीं हो जाता, खाद्य विभाग चावल की सप्लाई स्वीकार नहीं

करता। उन्होंने बताया कि साधारण चावल का कोटा, जो एथनॉल तथा डिस्टिलरी में उपयोग होता है, बहुत कम है, जिससे कुटाई शुरू नहीं हो पा रही है। इस संबंध में जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद दुबे ने बताया कि फोर्टिफाइड चावल के लैब परीक्षण की प्रक्रिया लंबी होने के कारण इसकी उपलब्धता में देरी हो रही है। लैब से गुणवत्ता जांच पूरी होते ही चावल की सप्लाई राइस मिलों को शुरू कर दी जाएगी। फोर्टिफाइड चावल पोषण युक्त चावल होता है, जिसमें फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन बी-12 मिलाया जाता है। इसे चावल में पीसकर मिलाया जाता है और फिर पुनः चावल के रूप में तैयार किया जाता है। मिलरों को प्रति क्विंटल धान पर एक किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल की मात्रा मिलानी होती है।

समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ललितपुर। भारतीय किसान संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जाखलौन पम्प नहर को फुल गेज, 5 पम्प चलाने के लिए तैयार, अमरपुर, रसोई, डिबाई आदि सभी माइनरों में पानी पहुंचाने की मांग उठायी। बताया कि राजघाट की उपरी व

निचली नहर का पानी टेल तक पानी पहुंचाया जाए। बिजली दस घंटा लगातार दी जाए, राजघाट, दैलवारा फीडर की बिजली पूरे दिन काटी जा रही है जिसे बंद किया जाए। और दिन में बिजली दी जाए, बिजली जाते ही जिओ व बीएसएनएल के नेटवर्क चले जाते हैं, जिसे ठीक कराया जाए। फसल बीमा का पिछले वर्ष का एक सौ दो

करोड़ रुपए दिलाए जाए और 2025 खरीफ बीमा हजारों किसानों को नहीं मिला जिसे शीघ्र दिलाया जाए। ज्ञापन पर केहरसिंह बुंदेला, सोहनलाल विश्वकर्मा, कृष्णकांत कांकर, उदल सिंह, तिलकराम कौशिक, भरतसिंह, चंदनसिंह, दीपचंद, रघुवीर सिंह, मनोज, भूपेंद्र, गोकुल, सूखा आदि मौजूद रहे।

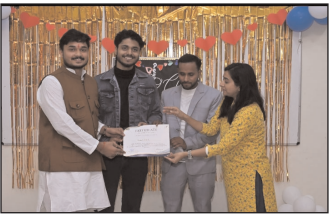
संक्षिप्त खबरें

यूपी-महाराष्ट्र: आधार अब जन्म प्रमाणपत्र का सबूत नहीं, एसआईआर के बीच यह आदेश



ब्यूरो प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यजना विभाग के विशेष सचिव अमित बंसल ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म प्रमाणपत्र नहीं माना जा सकता। यह फैसला राज्य की करोड़ों जनता, खासकर गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जहां आधार ही एकमात्र पहचान दस्तावेज है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह नीतिगत झटकेपर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की पिछली राय से मेल खाता है? आधार जो कभी सरकारी योजनाओं की 'शत' था, अब 'बाधा' बन गया है। उसके महत्व को अदातन से लेकर सरकार तक ने घटा दिया है। यूपी सरकार के आधार वाले फैसले पर इसलिए ध्यान गया है क्योंकि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। अगले चरण में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटेंगे, उनसे प्रमाण मांगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बिहार एआईआर के दौरान चुनाव आयोग से कह चुका है कि वो आधार को 12वें प्रमाणपत्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें। लेकिन यहां अब तकनीकी सवाल आ गया है। एसआईआर में जन्म तिथि सबसे महत्वपूर्ण नुस्ता है। इसका मतलब यह हुआ कि यूपी में एसआईआर के अगले चरण में जो जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर आधार जमा कराएगा, वो फॉर्म माना ही जाएगा, क्योंकि यूपी में आधार अब जन्म तिथि का प्रमाण नहीं रहा। यह महत्वपूर्ण तकनीकी सवाल है, जिसकी आंच यूपी में अगले चरण के एसआईआर में महसूस की जाएगी। महाराष्ट्र में भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड को दस्तावेज नहीं माना जाएगा और अगस्त 2023 के अधिनियम संशोधन के बाद केवल आधार कार्ड के जरिए बने सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला अवैध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को रोकने के लिए लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संधि प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, अब तक ये प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों, उप-विभागीय अधिकारियों, जिला आयुक्तों और संभागीय आयुक्तों को 16-सूत्रीय सत्यापन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पत्रकार कृष्ण चन्द्र शुक्ल के बेटे प्रशांत शुक्ल ने क्षेत्र का नाम किया रोशन



ब्यूरो प्रयागराज। विकासखंड शंकरगढ़ के लालापुर भट्टपुर हाल मुकाम निरुला नगर शंकरगढ़ निवासी प्रशांत शुक्ला पुत्र कृष्ण चंद्र शुक्ला ने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है।आगे बताते चलें कि, प्रशांत शुक्ला अभी तक कई प्रदेशों में शतरंज में जीती हासिल कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी।उसके उपरांत आज जियले यूनिवर्सिटी मथुरा से बीटेक कर रहे छात्र प्रशांत शुक्ला ने 30 अक्टूबर को मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित कोविट प्रतियोगिता में भाग ले रहे कई प्रदेशों के लोगों के मध्य फर्स्ट पोजीशन हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया । इसी प्रकार 8 नवंबर को बिट्स मिलाना गजस्थान में आयोजित पैर इंडिया कविता प्रतियोगिता में टॉप 4 में शामिल किया गया । इस प्रतियोगिता में उन्हें भारत के सबसे बड़े बिरला इंस्टीट्यूट प्रॉवेंचेर यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ । इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि अंकुश श्रीवास्तव एवं अंग्रेजी कवि जिनी वर्मा भी मौजूद रही । 118 नवंबर को जीएनए यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी कविता प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग कर रहे कई देश प्रदेश के लोगों एवं संस्कृति यूनिवर्सिटी , शास्व यूनिवर्सिटी ,हिंदुस्तान कॉलेज ,जीएल बजाज एवं कई अन्य देश के लोग एवं विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के मध्य कविता प्रतियोगिता में भी प्रशांत शुक्ला फर्स्ट पोजीशन लाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई । इसके अलावा ब्रिजित इंडियन आईस्कॉल पोप्ट प्रतियोगिता दिल्ली भारतीय विद्यापीठ में 21 दिसंबर को देश भर के प्रतिभाग में प्रौका पाने वाले 12 लोगों में प्रशांत शुक्ला का नाम अव्वल दर्जे पर अंकित किया गया । क्षेत्र देश प्रदेश में जीत हासिल करने वाले प्रशांत शुक्ला को ब्रिज इंटरनेशनल फर्स्ट पोजीशन में अपना नाम अंकित करने पर जियले यूनिवर्सिटी मथुरा के डीन हिमंशु शर्मा ने प्रशांत शुक्ला को प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि आज हमें गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय में ऐसे ही होनहार छात्रों की आवश्यकता है जो कि अपनी लगन मेहनत परिश्रम से विद्यालय का नाम रोशन करते हैं और हम आशा करते हैं कि यह हमेशा इसी तरह विद्यालय का नाम रोशन करते रहें।

आरपी एक्ट के तहत मौजूदा प्रक्रिया मान्य नहीं, चुनाव आयोग एसआईआर को सही ठहराने के लिए अनुच्छेद 324 पर भरोसा नहीं कर सकता

● याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (चुनाव आयोग) द्वारा किए जा रहे इलेक्शन रोल्स के स्पेशल इंटीस रिजिजन (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग के पास रिजिजेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, 1950 (RP Act) के तहत स्क्रू कर मौजूदा तरीके से करने की पावस नहीं हैं। सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि चुनाव एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग, एसआईआर को सही ठहराने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत अपनी पूरी शक्ति का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि एक बार जब यह फील्ड पार्लियामेंटी लॉ (RP Act) के तहत आ जाता है तो चुनाव आयोग को कानून के अनुसार काम करना होता है। सिंघवी ने बताया कि एसआईआर के लिए एन्यूमरेशन फॉर्मस को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। RP Act और रूलस एन्यूमरेशन फॉर्म को मान्यता नहीं देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (RJD MP मनोज झा के लिए) ने यह देखते हुए जोर देकर कहा कि एसआईआर प्रोसेस असल में गलत है, क्योंकि वोटर को यह साबित करने

मेजा ऊर्जा निगम को आन्दोलन कारियों से नहीं मिला मांग पत्र, पक्ष पहले ही था स्पष्ट



ब्यूरो प्रयागराज। यमुनावर (मेजा) तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ऊर्जा निगम परियोजना का मुख्य द्वार और टनलशिप सामान्य स्थिति में रहे संयुक्त अधिधान का सफल आयोजन उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति, लखनऊ शाखा प्रयागराज एवं पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं विद्यालय स्टाफ की भारी उपस्थिति रही। यातायात विषय पर उप निरीक्षक इंद्रपाल वर्मा द्वारा उपस्थित हजारों छात्रों को यातायात नियमों, संकेतों एवं सुरक्षित वाहन में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।एसएमसीएल द्वारा प्रम सलैया कला में कोई नया निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड की इकाई मेजा थर्मल पावर परियोजना स्टेज टुवू के विस्तार के लिए प्रम सलैया कला में सक्सी भूमि का पुनर्गठन किया जा सकता है, जो अभी प्रक्रियाधीन है।रोजगार के सम्बन्ध में भू स्वामियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, सविदा जॉर्जसियों में अवसर, सविदा के अंतर्गत जीप लगाने तथा सहकारी समिति के माध्यम से सविदा कार्य हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव 7 सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बाकी चुनाव नोटिफाई किए जाएं, लेकिन रिजर्वेशन 50% से ज्यादा न हो

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को उन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नोटिफाई करने से रोक दिया, जहां चुनाव अभी नोटिफाई होने बाकी हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन पहले ही नोटिफाई हो चुका है, उनके चुनाव रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC रिजर्वेशन को चुनौती देने वाली रिट याचिका को सुनवाई कर रही थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन के सीनियर एडवोकेट बरनबीर सिंह ने बेंच को बताया कि 246 म्युनिसिपल काउंसिल और 42 नगर पंचायत हैं, जहां चुनाव प्रोसेस शुरू हो चुका है। वोटिंग 2 दिसंबर को होनी है। ? इनमें से 40 म्युनिसिपल काउंसिल और 17 नगर पंचायत ऐसी हैं, जहां रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है। हालांकि, 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 32 जिला पंचायत और 346 पंचायत समितियों के चुनाव अभी नोटिफाई होने बाकी हैं। मामलों को 12 जनवरी को बेंच को भेजते हुए और 21 जनवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए बेंच ने पहले से नोटिफाई किए गए चुनाव कराने की इजाजत दी। बेंच ने आदेश दिया, 'इस बीच म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के चुनाव नोटिफाई किए गए शेड्यूल के हिसाब से हो सकते हैं। हालांकि, जिन स्थानीय निकाय चुनाव में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है, उनके नतीजे रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर होंगे।' बेंच ने स्पष्ट को बाकी स्थानीय निकाय के चुनाव

के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत है कि उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था। उन्होंने आगे कहा कि वोटर की नागरिकता तय करना बीएलओ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जो इस पद पर नियुक्त कोई स्कूल टीचर भी हो सकता है। एक उदाहरण का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा, 'गिनने वाले ने उससे (वोटर से) पूछा, प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे पिता का जन्म कब हुआ था? मुझे इसका सबूत दो...तुम यह कैसे दोगे?' हालांकि, जस्टिस बागची ने बीच में टोकते हुए कहा कि कोर्ट इस मुद्दे को 'नॉर्मेटिव लेवल' पर समझना चाहता है और क्या यह RP Act और संविधान और नागरिकता एक्ट जैसे दूसरे जुड़े हुए कानूनों के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों के मुताबिक है। जस्टिस बागची ने कहा कि वोटर आधार जैसे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, जिसकी कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर के हिसाब से इजाजत दी है। सिब्बल ने कई वोटरों के अनपढ़/बिना पढ़े-लिखे होने की जमीनी हकीकत का जिक्र करते हुए कहा: 'पासपोर्ट वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट, वह नहीं दिखा पाएगा, यही मैं कह रहा हूँ... अगर वह 2003 और 2007 के बीच पैदा हुआ है तो दो बातें साबित करनी होंगी: (1) भारत का नागरिक होना और (2) वह गैर-कानूनी माइग्रेंट नहीं है - आप यह जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (RJD MP मनोज झा के लिए) ने यह देखते हुए जोर देकर कहा कि एसआईआर प्रोसेस असल में गलत है, क्योंकि वोटर को यह साबित करने

सनबीम स्कूल नैनी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नैनी, प्रयागराज: यातायात माह नवंबर 2025 के अंतर्गत 28वें दिन यमुनानगर नैनी स्थित सनबीम स्कूल एवं कॉलेज में साइबर अपराध,मिशन शक्ति एवं यातायात जागरूकता अधिधान का सफल आयोजन उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति, लखनऊ शाखा प्रयागराज एवं पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं विद्यालय स्टाफ की भारी उपस्थिति रही। यातायात विषय पर उप निरीक्षक इंद्रपाल वर्मा द्वारा उपस्थित हजारों छात्रों को यातायात नियमों, संकेतों एवं सुरक्षित वाहन में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।एसएमसीएल द्वारा प्रम सलैया कला में कोई नया निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड की इकाई मेजा थर्मल पावर परियोजना स्टेज टुवू के विस्तार के लिए प्रम सलैया कला में सक्सी भूमि का पुनर्गठन किया जा सकता है, जो अभी प्रक्रियाधीन है।रोजगार के सम्बन्ध में भू स्वामियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, सविदा जॉर्जसियों में अवसर, सविदा के अंतर्गत जीप लगाने तथा सहकारी समिति के माध्यम से सविदा कार्य हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।



की जानकारी दी। वहीं उप निरीक्षक सदान यादव ने कानून व्यवस्था एवं नागरिक कर्तव्यों पर उपयोगी जानकारी साझा की। यह कार्यक्रम चेयर मैन कमलेश श्रीवास्तव व श्री आर. एस. वर्मा आईएसएस पूर्व मंडल आयुक्त वाइस चैयरमैन समिति के निर्देशन में चलाया जा रहा है समिति सचिव संतोष कुमार ने विद्यार्थियों से अपील किया कि वे शिक्षा को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाएं और प्राप्त जानकारी को अपने परिवार, रिश्तेदारों एवं समाज के बीच साझा करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा हम सभी का नैतिक दायित्व है। विद्यालय परिसर में शासन द्वारा जारी टोल फ्री नंबरे के स्लोगन युक्त बैनर भी प्रदर्शित किए गए। शासन द्वारा जारी प्रमुख टोल फ्री नंबर 112 आपातकालीन सेवा, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन, 1090 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, 1091



‘एन मास/व्कैन्टे एक्सरसाइज’ के तौर पर। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘भारत में पहले कभी, न ROPA के तहत और न ही नियमों के तहत, आपको एन मास अधिकार नहीं दिया गया?’ सिंघवी के अनुसार, रोल पर किसी व्यक्ति के नाम के वरिफिकेशन को चुनौती देने के मुद्दे को फॉर्म 7 (मौजूदा इलेक्शन रोल में एनरोल किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी किसी आपत्ति पर विचार कर रहा है तो उसे सिटिजनशिप एक्ट के तहत इस मुद्दे को तय करने के लिए मामले को केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय को भेजना चाहिए। ‘इस प्रवधान पर आपत्ति जताते हुए सिब्बल ने कहा, ‘यही वह बात है, जिसे वे (चुनाव आयोग) मेरे लॉईस को मानने के लिए मनावे की कोशिश कर रहे हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘स्कूल में एक टीचर को BLO के तौर पर अपॉइंट करना एक खतरनाक बात है ताकि उसे यह अधिकार (नागरिकता पर विचार करने का) मिल सके। ‘ दूसरे याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए डॉ. एएम सिंघवी ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि एसआईआर प्रोसेस को कानूनी कानूनों का कोई स्पेक्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफ/रहने की जगह वगैरह के वरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह ‘यह तय करने के लिए वरिफिकेशन है कि वे नागरिक हूं या नहीं।’ सिंघवी ने फिर जोर देकर कहा कि एसआईआर को आरपी एक्ट 1950 (ROPA) और उससे जुड़े नियमों की स्वीम के तहत ‘ईंडिविजुअल एक्सरसाइज’ के तौर पर देखा गया, न कि



महिला पुलिस हेल्पलाइन, 181 महिला सहायता सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 की भी जानकारी दी गई। उकृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन हसन ए नकवी द्वारा किया गया। विद्यालय की उप प्रधानाचार्या प्रमिला सिंह ने आए हुए समस्त अधिकारियों एवं समिति पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया। विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य का विशेष सहयोग उल्लेखनीय रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना विकसित करना एवं समाज को सुरक्षित, अपराधमुक्त बनाने की दिशा में सशक्त पहल करना रहा।

दिल्ली में ‘दमघौंटू’ हवा की मार जारी, गंभीर श्रेणी में हवा,AQI 400 के पार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह भी गंभीर वायु प्रदूषण के साथ शुरू हुई। जो पिछले करीब 15 दिनों से लगातार जारी है। राजधानी की हवा का औसत AQI आस 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। यह स्तर सीधे ‘हेजर्डस’ यानी स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। राजधानी में यह स्थिति अब सिर्फ प्रदूषण नहीं, बल्कि स्वास्थ्य आपातकाल जैसी बन चुकी है। इसी बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने दिल्ली के प्रदूषण पर तुरंत एक्शन के लिए पीएनओ से गुहार लगाई है। अपने सोशल मीडिया ‘X’ अकाउंट पर उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण की महामारी से तुलना करते हुए चिंता जताई है और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। किरण बेदी ने जहां दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर पीएमओ से हस्तक्षेप की मांग की है, वहीं उन्होंने ऐसे पांच कारण भी बताए हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। किरण बेदी ने दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का पहला कारण बताते हुए लिखा ‘भारत में वायु प्रदूषण का संकट हर साल दोहराया जाता है, क्योंकि सरकारें मूल कारणों

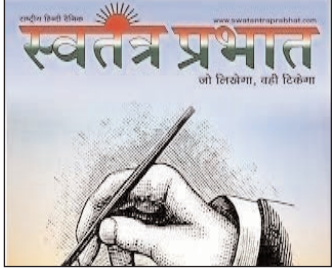
तरीके से रोल का रिविजन है, इसमें एक साथ कोई शक्ति नहीं है। ‘सिंघवी ने बताया कि मौजूदा प्रोसेस में कुछ ‘रेडिशियल खासियतें’ हैं: (1) यह हमेशा राज्य के हिसाब से कम से कम होता है, और जिन राज्यों से उन्होंने शुरुआत की है, वे भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं - बिहार और अब रोल में नाम शामिल करने/हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए एलीकेशन फॉर्म) के तहत नियतया गया। सिंघवी के अनुसार, फॉर्म 7 के बावजूद, एक साथ वरिफिकेशन करना आर्टिकल 327 के खिलाफ होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह ‘बड़े पैमाने पर वरिफिकेशन’ कभी भी चुनाव आयोग को नहीं दिया गया, जिसे अब वह आर्टिकल 324 के तहत ढूँढने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, सीजेआई ने कहा, ‘आपके तर्क के अनुसार, चुनाव आयोग के पास कभी भी एसआईआर की शक्ति नहीं होगी। ‘सिंघवी ने साफ किया कि चुनाव आयोग की शक्ति सीमित है; वह यह नहीं कह सकता कि हम लोगों को रोल पर मान रहे हैं और हमारी लिस्ट के अनुसार वरिफिकेशन के बाद ही इसकी पुष्टि होगी।उन्होंने आगे कहा, ‘एसआईआर एक सीमित चुनाव क्षेत्र में व्यक्तिगत/द्विपक्षीय

भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति के आंकड़ों पर सवाल, IMF ने सी ग्रेड दिया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी नवीनतम समीक्षा में भारत को उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और एकाउंट्स आंकड़ों की गुणवत्ता और कार्याप्रणाली के लिए ‘सी’ रेटिंग दी है। यह दूसरी सबसे निचली श्रेणी है। भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति की हकीकत सामने है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की अपनी वार्षिक समीक्षा में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और सकल मूल्य वर्धित (GVA) सहित महत्वपूर्ण आंकड़ों को ‘B’ ग्रेड दिया है। यह उपलब्ध अधिकारियों एवं समिति पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया। विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य का विशेष सहयोग उल्लेखनीय रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना विकसित करना एवं समाज को सुरक्षित, अपराधमुक्त बनाने की दिशा में सशक्त पहल करना रहा।

सरस्वती विद्या मंदिर माधव ज्ञान केंद्र में वार्षिक निरीक्षण



नैनी, प्रयागराज। सरस्वती विद्या मंदिर माधव ज्ञान केंद्र में वार्षिक निरीक्षण विद्या भारती की योजना अनुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 27,28 एवं 29 नवम्बर को विद्यालय के वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम तय हुआ। जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर के प्रधानाचार्य राकेश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में उनकी टोली के बंधु रामशंकर तिवारी अंग्रेजी के प्रवक्ता, अखिलेश प्रताप सिंह गणित के प्रवक्ता, कोशलेंद्र भौतिक के प्रवक्ता, यशी अग्रहरी प्रवक्ता अर्थ शास्त्र एवं श्रेया तिवारी कार्यालय प्रमुख ने विद्यालय का तीन दिवसीय निरीक्षण बारीकी से किया। निरीक्षण के अंतर्गत विद्यालय की प्रार्थना सत्र, माध्यवकाश, वंदे मातरम, कक्षा कक्ष का निरीक्षण ,पंजीयों का रखरखाव, विभिन्न विभागों की व्यवस्था, आचार्य का दायित्व, विद्यालय में छात्र संसद, कन्या भारती की सक्रियता, भौतिक ,रसायन एवं जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं सहित सभी बिंदुओं का सूक्ष्म अवलोकन किया ढ़ विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय कुमार मिश्र ने प्रार्थना सत्र में अतिथियों का परिचय कराया ,उपयुक्त निरीक्षण में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने-अपने कर्तव्य एवं दायित्व का शत प्रतिशत निर्वाह किया।

लेखा ऑफ़ेड जारी करने वाली है, जिससे यह मुद्दा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आईएमएफ ने विशेष रूप से यह टिप्पणी की है कि भारत के राष्ट्रीय खाते और मुद्रास्फीति के आंकड़े अनौपचारिक क्षेत्र और लोगों के खर्च करने के पैटर्न जैसे प्रमुख पहलुओं को पर्याप्त रूप से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। यानी अनौपचारिक क्षेत्र के आंकड़े जब तक स्पष्ट नहीं होंगे और लोग किस तरह खर्च कर रहे हैं, यह साफ नहीं होगा, तब तक सही मायने में आंकड़ों पर विश्वास करना मुश्किल है। जीडीपी के विपरीत, भारत की प्रमुख मुद्रास्फीति माप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Inde& - CPI), को आईएमएफ द्वारा ‘बी’ ग्रेड दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह ‘निगरानी के लिए व्यापक रूप से पर्याप्त’ है, लेकिन कुछ कमियाँ फिर भी मौजूद हैं। सीपीआई को ‘बी’ ग्रेड मिलने का मुख्य कारण इसका पुराना आधार वर्ष (2011-12), आइटम बास्केट और भार है। आईएमएफ के अनुसार, सीपीआई बास्केट वर्तमान खर्च करने की आदतों को सटीक रूप से दर्शाने में विफल है।



है। ‘किरण बेदी ने पोस्ट में लिखा ‘यह बहुत तत्कालीन देने वाला और डिप्रेंसिंग है। PMO स्तर, कृपया तुरंत हस्तक्षेप करें।’ एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा ‘यह प्रदूषण अब महामारी जैसे हालात पैदा कर रहा है और इसके लिए बड़े स्तर पर को-ऑर्डिनेशन और एक्शन की जरूरत है।’ उन्होंने यह भी सलाह दी कि प्रदूषण से निपटने के लिए कोविड-19 की तरह सिस्टमैटिक और गंभीर स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए PMO में 25 नवंबर को एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए तेज और सख्त एक्शन पर चर्चा की गई। बैठक में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर डिपेंडेंसी कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने, चार्जिंग स्टेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने की बात पर जोर दिया गया।

SAR देशवासियों के खिलाफ बड़ी साजिश-अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खुरब स्थिति में ले जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने ब्रह्मसंहार को ‘एसस’ पर एसआईआर प्रक्रिया का 20 सेकंड का एक वीडियो साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा, ‘ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। जनता जागरूक हो। आज वोट काट जा रहा है, कल को खेत-जमीन-मकान-राशन-जाति-आरक्षण से नाम काट दिया जाएगा। फिर बात खातों और मध्यम वर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी।’ अपने लंबे पोस्ट में यादव ने कहा, ‘ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खुरब स्थिति में ले जाएगी। ये समय जागने का है और एक-एक वोट बचाने का है।’ उन्होंने विपक्षी दलों के साथ ही रजाम में भाजपा के सहयोगी दलों का आह्वान करते हुए कहा, ‘हमारी सभी विपक्षी दलों और यहां तक कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी सहयोगी दलों से यह अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महा-पड्डन का पर्दाफाश करें।’ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इस दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खाना करेगी। इसलिए हमारी प्रत्येक देखावसी से अपील है कि सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी को रोकें।’ उन्होंने कहा, ‘भाजपा, भाजपा के सींगी-साथी और भाजपा सत्कार की तिकड़ी व निर्वाचन आयोग के कुछ भ्रष्ट लोग पूरी चुनावी व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने लिखा, ‘आइए हम सब मिलकर उन भाजपाइयों और उनके अपवित्रवादी सींगी-साथियों की संसाम लूट से देश को बचाएं और वोट के रूप में अपनी पहचान को भी बचाएं, नहीं तो कल को ये देशवासियों को ही परया साबित कर देंगे।’

सक्षिप्त खबरें

बनहरदी कोयला खनन परियोजना द्वारा बारी में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, 72 ग्रामीणों का हुआ नि:शुल्क नेत्र परीक्षण

चंदवा, झारखंड:- बनहरदी कोयला खनन परियोजना (पीवीयूएनएल) की ओर से सामुदायिक विकास कार्यों के तहत ग्राम बारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते शुक्रवार को नि:शुल्क नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना और नेत्र रोगों की पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करना था। शिविर में बारी, एने, रामपुर, सरली, बनहरदी सहित आसपास के कई गांवों से आए 72 ग्रामीणों का नेत्र परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराईं। ग्रामीणों ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएँ सीमित होने के कारण ऐसे शिविर उन्हें राहत प्रदान करते हैं। पीवीयूएनएल के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम का संचालन किया। परियोजना प्रबंधन की ओर से आर. वी. सिंह, महेश शंकर, अमरेश चंद्र राउल, विनेश कुमार, डॉ. मनीष देवदत्त एक्का, अमित द्विवेदी, पूजा और शुभंकर मंडल मौजूद थे। बारी पंचायत के मुखिया रविन उरांव और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामीणों ने पीवीयूएनएल से इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर आगे भी आयोजित करने की मांग की, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। आयोजन ने ग्रामीण समुदाय और परियोजना प्रबंधन के बीच संवाद और सहयोग को और मजबूत बनाया।

परेड की सलामी लेकर एसपी ने किया पुलिस लाइंस का निरीक्षण
चित्रकूट: पुलिस लाइंस में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक परेड का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने सलामी लेकर किया। इस दौरान उन्होंने परेड में शामिल रिक्तस्ट अफ़ीसियों और पुलिस बल को शारीरिक, मानसिक रूप से पिष्ट रहने और अनुशासन व तत्परता बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यायाम कराए और परेड की दौड़ भी कराई। परेड के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति जागरूक किया तथा प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। परेड के निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक ने परिवहन शाखा पहुंचकर डायल-112 पीआरवी सहित अन्य दो और चार पहिया वाहनों की स्थिति की समीक्षा की तथा आवश्यक सुधार व मरम्मत के निर्देश दिए। इसके अलावा एसपी ने आर्टीसी बैक, आवास परिसर, भोजनालय, मंदिर, अमरी और सीपीसी कैटीन का भी निरीक्षण कर स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। अंत में क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण कर सलामी ली और पुलिस कर्मियों का अर्दली रूम किया गया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर अरविन्द कुमार वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक राम शीष यादव, निरीक्षक आरटीसी शिवमूर्त यादव सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

सहकारिता विभाग में जल्द होगी 1089 पदों पर भर्ती, मंत्री ने अफसरों को दिया निर्देश

पटना। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने विभागीय रिक्तियों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने विभाग में रिक्तियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि सहकारिता विभाग के तहत कुल 1089 पदों की अधियाचना संवर्धित आयोगों को भेजी जा चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग को कुल 537 पदों और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 552 पदों की अधियाचना भेजी गई है। संबंधित पदों पर आयोगों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी किए जाने की उम्मीद है। बैठक में दी गई जानकारी के मुताबिक सहकारिता विभाग के राजपत्रित पदों के लिए 31 सहायक निबंधक एवं चार जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की 502 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, को भेजी जा चुकी है, जिसपर विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार अंकेक्षण के 198, आर्थुलिक के सात, निम्नगणिय लिपिक के 257 एवं कार्यालय परिचारी के 90 पदों की अधियाचना बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है।

पाकुड़ में दुर्गापूजा, काली पूजा एवं छठ पूजा-2025 का भव्य पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न

● **उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त ने शॉल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर समितियों को किया सम्मानित**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पाकुड़, झारखंड:- बाजार समिति, पाकुड़ में शुक्रवार को दुर्गापूजा, काली पूजा एवं छठ पूजा-2025 के शांतिपूर्ण एवं सफल आयोजन के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त महेश कुमार संश्रितिया, परियोजना निदेशक आईटीडीए अरुण कुमार एक्का, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी साईमन मरांडी, विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभुवन कुमार सिंह, नगर परिषद प्रशासक अमरेंद्र कुमार चौधरी सहित लिलेभर की पूजा समितियों के प्रतिनिधि एवं मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। उपायुक्त मनीष कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे डेढ़ महीने तक चले पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, नव-नियुक्त चौकीदारों और शांति समिति के सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने पूर्व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के योगदान के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया तथा वर्तमान एसपी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि कई पंडालों में जनकल्याण से जुड़े संदेश, स्वच्छता जागरूकता तथा रक्तदान को बढ़ावा देने वाले प्रयास विशेष रूप से प्रशंसनीय रहे। स्थानीय स्थानों पर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल सभी 'रक्तवीरो' को उन्होंने धन्यवाद दिया। अतिथियों ने बड़े, मध्यम और छोटे वर्ग के दुर्गापूजा पंडालों, काली



पूजा एवं छठ पूजा समितियों को शॉल ओढ़ाकर, मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
सम्मानित दुर्गापूजा पंडाल-2025: बड़े पंडाल (क्षमता 5000 से अधिक): आमड़ापाड़ा बाजार की दुर्गापूजा समिति और हिरणपुर डक बंगला दुर्गापूजा समिति को प्रथम पुरस्कार, पाकुड़ राजापाड़ा तथा सरस्वती पुस्तकालय पाकुड़ की दुर्गापूजा समितियों को द्वितीय पुरस्कार, जबकि पाकुड़िया बंगाली टोला तथा महेशपुर थाना पाड़ा की दुर्गापूजा समितियों को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
मध्यम पंडाल (क्षमता 1000-5000): तारपुर, हिरणपुर की दुर्गापूजा समिति और नारी शक्ति दुर्गापूजा समिति, पाकुड़ को प्रथम पुरस्कार, महाकाल शक्तिपीठ तलवडांगा तथा पाकुड़ सदभावना समिति को द्वितीय पुरस्कार, जबकि कालिकापुराण, पाकुड़ और तोड़ाई, हिरणपुर की दुर्गापूजा समितियों को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
पंडाल (क्षमता 1000-1500): काठशाला, चांदपुर, रेलवे स्टेशन, रेलवे कालोनी, शमशान काली राजापाड़ा, डांगपाड़ा, लिट्टीपाड़ा, तालपहाड़ी लिट्टीपाड़ा, बासमती आमड़ापाड़ा, सिलमपुर महेशपुर, शहरग्राम, रोलग्राम, बाहापुर, मोगलाबांध तथा बनोग्राम सहित सभी छोटे पंडालों को सात्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।

खजूरडंगाल पंचायत में उपासना मरांडी की पहल पर लगा नया ट्रांसफार्मर, गांव में लौटी रौशनी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पाकुड़िया, पाकुड़, झारखंड:- पाकुड़िया प्रखंड के खजूरडंगाल पंचायत में बीते दिनों ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने के बाद अंधेरे में डूबे ग्रामीणों के घरों में फिर से उजाला लौट आया है। ग्रामीणों की पेशानी रिक्तस्ट आरक्षियों और पुलिस बल को शारीरिक, मानसिक रूप से पिष्ट रहने और अनुशासन व तत्परता बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यायाम कराए और परेड की दौड़ भी कराई। परेड के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति जागरूक किया तथा प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। परेड के निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक ने परिवहन शाखा पहुंचकर डायल-112 पीआरवी सहित अन्य दो और चार पहिया वाहनों की स्थिति की समीक्षा की तथा आवश्यक सुधार व मरम्मत के निर्देश दिए। इसके अलावा एसपी ने आर्टीसी बैक, आवास परिसर, भोजनालय, मंदिर, अमरी और सीपीसी कैटीन का भी निरीक्षण कर स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। अंत में क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण कर सलामी ली और पुलिस कर्मियों का अर्दली रूम किया गया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर अरविन्द कुमार वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक राम शीष यादव, निरीक्षक आरटीसी शिवमूर्त यादव सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

केंद्र प्रायोजित 50 शैया प्री-फेब्रिकेटेड अस्पताल व 38 पीसीसी सड़कों का हुआ भव्य उद्घाटन

● **उपायुक्त मनीष कुमार और विधायक प्रो. स्टेफन मरांडी ने किया लोकार्पण**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पाकुड़िया, पाकुड़, झारखंड:- पाकुड़िया प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में केंद्र प्रायोजित 50 शैया क्षमता वाले प्री-फेब्रिकेटेड अस्पताल का विधिवत उद्घाटन तथा 38 पीसीसी सड़कों का शिलान्यास 28 नवंबर को समारोहपूर्वक किया गया। उपायुक्त मनीष कुमार एवं महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टेफन मरांडी ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर दोनों योजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के हिा में लगातार योजनाओं का स्वागत विशेषकर महिलाओं की उपस्थिति ने

स्वास्थ्य केंद्र की साहियाओं ने पारंपरिक नृत्य एवं स्वागत गीत के माध्यम से किया। उद्घाटन समारोह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. भरत भूषण भगत, गंगा शरण साह, मंजर आलम, वसीम राजा सहित सभी मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बनर्जी, जिला परिषद अध्यक्ष जुलिखटमुनी, प्रखंड प्रमुख कालीदास मरांडी, बीस सूत्री प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसवा, झामुमो के हरिवंश चौबे, सांसद प्रतिनिधि खुर्शीद आलम तथा जिला काटकर और नारियल फोड़कर दोनों ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों, स्थल पर आगतुक अतिथियों का स्वागत

'गोली मारने' तक पहुंची कांग्रेस नेताओं की तकरार, बिहार में हार पर तीखी बहस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पाकुड़िया, पाकुड़, झारखंड:- झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शुक्रवार को प्रखण्ड के लागडुम पंचायत स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त पाकुड़ मनीष कुमार, महेशपुर विधायक प्रो. स्टेफन मरांडी तथा जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती जुलिखटमुनी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रो. मरांडी ने ग्रामीणों से राज्य सरकार द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के हित में लगातार योजनाएँ चला रही है और इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो रहा है। उपायुक्त मनीष कुमार ने सेवा गारंटी अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालते

चित्रकूट पुलिस बेड़े में शामिल हुए 29 नए पीआरवी वाहन, एसपी ने दिखाई हरी झंडी

चित्रकूट: जनपद में आपातकालीन पुलिस सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से डायल-112 मुख्यालय से भेजे गए 29 नए पीआरवी वाहनों को शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कॉर्पियो और इनोवा मॉडल के ये आधुनिक चार पहिया वाहन पुलिस सेवा को तेज, सहज और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एसपी ने बताया कि इन नए वाहनों के शामिल होने से डायल-112 का रिसांस टाइम कम होगा। साथ ही अपराध नियंत्रण तथा त्वरित कार्रवाई में बेहतर परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि तैनात पीआरवी वाहनों की संख्या बढ़ने से पुलिस की पहुंच प्रत्येक क्षेत्र तक और तेजी से संभव होगी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सत्याल सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर अरविन्द कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी यातायात यामीन अहमद, प्रतिसार निरीक्षक राम शीष यादव, प्रभारी डायल-112 शम्भू दयाल मौर्ग, एमटी प्रभारी राम सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

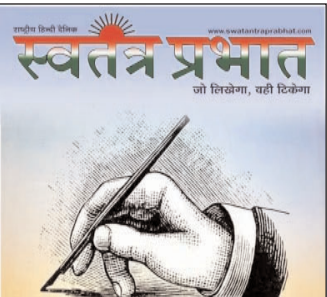
कर्मज ग्राउंड में दो दिवसीय आर्चरी सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ

● **तीरंदाजी प्रतियोगिता में उमड़ा खिलाड़ियों का उत्साह, राष्ट्रीय मंच तक तैयारी देने का संकल्प**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हजारीबाग, झारखंड:- सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत कर्मज ग्राउंड में आयोजित दो दिवसीय आर्चरी (तीरंदाजी) प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को उत्साह और उत्साह के बीच हुआ। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 तीनों आयु वर्गों में जिले के कुल 130 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। जिला आर्चरी संघ द्वारा सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर आयोजित यह आयोजन हजारीबाग की उभरती खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो रहा है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता ने तीरंदाजी कर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि विनोद झुनझुनवाला, सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी, जिला सांसद प्रतिनिधि अजय कुमार साहू, बंटी तिवारी, जयप्रकाश, कोच मनोज कुमार एवं रुपम कुमार उपस्थित थे। उद्घाटन से पूर्व अतिथियों

अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार



चित्रकूट: जनपद में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रैपुरा के उपनिरीक्षक अखिलेश सिंह व उनकी टीम उपनिरीक्षक सुभाषराय व आरक्षी बब्बू राजा द्वारा एक आरोपी को 20 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

चित्रकूट: जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को केंद्रीय ज्वाइंट डायरेक्टर मनीषा चंद्रा और मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर के साथ भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपी.ओ.) के अंतर्गत संचालित कर्वी ऑर्गेनिक एफपी.ओ. का निरीक्षण किया। यहां अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे मिलेट्स (श्री अन्न) आधारित उत्पादों का अवलोकन किया और उनके कार्य की सराहना की। एफपी.ओ. परिसर में डीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे सावा चावल, कोदो चावल, रागी, ज्वार, बाजरा आटा, दलहन, तिलहन, काला गेहूं दलिया, कठिया गेहूं दलिया समेत अनेक जैविक खाद्य उत्पादों का अवलोकन किया। एफपी.ओ. के सीईओ सत्येंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार जैविक उत्पाद दिल्ली, उत्तराखंड, लखनऊ, बांदा, महोबा, सीधी बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।



हए कहा कि यह अधिनियम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर है। इस अवसर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बनर्जी ने प्रखण्ड अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के हित में लगातार योजनाएँ चला रही है और इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो रहा है। उपायुक्त मनीष कुमार ने सेवा गारंटी अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालते

चित्रकूट पुलिस बेड़े में शामिल हुए 29 नए पीआरवी वाहन, एसपी ने दिखाई हरी झंडी

चित्रकूट: जनपद में आपातकालीन पुलिस सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से डायल-112 मुख्यालय से भेजे गए 29 नए पीआरवी वाहनों को शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कॉर्पियो और इनोवा मॉडल के ये आधुनिक चार पहिया वाहन पुलिस सेवा को तेज, सहज और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एसपी ने बताया कि इन नए वाहनों के शामिल होने से डायल-112 का रिसांस टाइम कम होगा। साथ ही अपराध नियंत्रण तथा त्वरित कार्रवाई में बेहतर परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि तैनात पीआरवी वाहनों की संख्या बढ़ने से पुलिस की पहुंच प्रत्येक क्षेत्र तक और तेजी से संभव होगी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सत्याल सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर अरविन्द कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी यातायात यामीन अहमद, प्रतिसार निरीक्षक राम शीष यादव, प्रभारी डायल-112 शम्भू दयाल मौर्ग, एमटी प्रभारी राम सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

कर्मज ग्राउंड में दो दिवसीय आर्चरी सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ

● **तीरंदाजी प्रतियोगिता में उमड़ा खिलाड़ियों का उत्साह, राष्ट्रीय मंच तक तैयारी देने का संकल्प**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हजारीबाग, झारखंड:- सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत कर्मज ग्राउंड में आयोजित दो दिवसीय आर्चरी (तीरंदाजी) प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को उत्साह और उत्साह के बीच हुआ। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 तीनों आयु वर्गों में जिले के कुल 130 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। जिला आर्चरी संघ द्वारा सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर आयोजित यह आयोजन हजारीबाग की उभरती खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो रहा है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता ने तीरंदाजी कर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि विनोद झुनझुनवाला, सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी, जिला सांसद प्रतिनिधि अजय कुमार साहू, बंटी तिवारी, जयप्रकाश, कोच मनोज कुमार एवं रुपम कुमार उपस्थित थे। उद्घाटन से पूर्व अतिथियों

उत्कर्मित मध्य विद्यालय नावाडीह में महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, वृक्षारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हजारीबाग, झारखंड:- उत्कर्मित मध्य विद्यालय नावाडीह में शुक्रवार को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. जहांगीर अंसारी ने शिक्षकों व स्थानीय वार्ड सदस्या श्वेता ओझा के साथ मिलकर फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इसके उपरांत विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानाध्यापक ने छात्रों को महात्मा फुले के जीवन, उनके संघर्ष और सामाजिक योगदान पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फुले ने जातिवाद, अस्पृश्यता और लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। वर्ष 1848 में फुले दंपति द्वारा लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था, जिसने सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम रखा। वर्ष 1873 में

ज्वाइंट डायरेक्टर और डीएम ने जाना किसान उत्पादक संगठन का हाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चित्रकूट: जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को केंद्रीय ज्वाइंट डायरेक्टर मनीषा चंद्रा और मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर के साथ भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपी.ओ.) के अंतर्गत संचालित कर्वी ऑर्गेनिक एफपी.ओ. का निरीक्षण किया। यहां अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे मिलेट्स (श्री अन्न) आधारित उत्पादों का अवलोकन किया और उनके कार्य की सराहना की। एफपी.ओ. परिसर में डीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे सावा चावल, कोदो चावल, रागी, ज्वार, बाजरा आटा, दलहन, तिलहन, काला गेहूं दलिया, कठिया गेहूं दलिया समेत अनेक जैविक खाद्य उत्पादों का अवलोकन किया। एफपी.ओ. के सीईओ सत्येंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार जैविक उत्पाद दिल्ली, उत्तराखंड, लखनऊ, बांदा, महोबा, सीधी बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

बलिया: दूल्हा-दुल्हन का स्टेज अचानक ढहा, बीजेपी जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद सहित कई लोग गिरे; बड़ा हादसा टला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया- आयोजित एक शादी के रिसेशन में बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। वर-वधु को आशीर्वाद देने के दौरान अचानक स्टेज भरभराकर ढह गया, जिससे दूल्हा-दुल्हन समेत मंच पर मौजूद सभी लोग नीचे जा गिरे। स्टेज पर बीजेपी जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद और अन्य नेता भी मौजूद थे। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

क्या हुआ था?- शहर के रामलीला मैदान में बीजेपी नेता अभिषेक सिंह 'इंजीनियर' के भाई का रिसेशन आयोजित था। समारोह में बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, बलिया के पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक के प्रतिनिधि विश्राम सिंह, और बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री सुरजीत सिंह सहित कई नेता पहुंचे थे। दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे और लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। इसी दौरान कई नेता एक साथ मंच पर चढ़ गए। दूल्हा सभी के पैर छूकर आशीर्वाद ले ही रहा था कि अचानक स्टेज का संतुलन बिगड़ा और पूरा मंच भरभराकर नीचे गिर गया।



ने मैदान में मौजूद बच्चों से बातचीत की, उनके उत्साह की सराहना की और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। सांसद मनीष जायसवाल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, 'हजारीबाग की युवा प्रतिभाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की मजबूत तैयारी देना है। 'उन्होंने कहा कि जिले के खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन और प्रतियोगिता वातावरण उपलब्ध कराना उनका संकल्प है। मुख्य अतिथि उमेश प्रसाद मेहता ने कहा कि अवसर पर विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि विनोद झुनझुनवाला, सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी, जिला सांसद प्रतिनिधि अजय कुमार साहू, बंटी तिवारी, जयप्रकाश, कोच मनोज कुमार एवं रुपम कुमार उपस्थित थे। उद्घाटन से पूर्व अतिथियों



उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दलों व पिछड़े वर्ग के लिए न्याय की नई राह विकसित की। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि फुले विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे और उन्होंने विधवाओं के आश्रय व शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए। डॉ. भीमराव अंबेडकर भी उन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मानित करते थे। महात्मा फुले का निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ था। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में शिक्षक लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था, जिसने सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम रखा। वर्ष 1873 में



रहे हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का बेहतर अवसर मिला रहा है। इस दौरान किसान सुशील कुमार ने कहा कि मिलेट्स प्रोसेसिंग मशीन की आवश्यकता है जिससे उत्पादन और प्रसंस्करण की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा। इस पर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा कि जनपद में मिलेट्स कैटीन और मिलेट्स स्टोर स्थापित किए जाएंगे, इससे मिलेट्स उत्पादों की बिक्री और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। केंद्रीय ज्वाइंट डायरेक्टर मनीषा चंद्रा ने रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि जैविक विधि से तैयार अनाज का



अफरा-तफरी के बीच सभी सुरक्षित निकाले गए- मंच टूटते ही कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और गिर चुके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। एक कार्यकर्ता को हल्की चोटों के अलावा कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। दूल्हा-दुल्हन भी सुरक्षित हैं।

जिलाध्यक्ष ने बताया — कमजोर था मंच- घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्र ने कहा- 'मंच कमजोर था, और आवश्यकता से अधिक लोग चढ़ गए थे। इसी वजह से मंच अचानक टूट गया। संयोग अच्छा था कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। '



बताया। पहले दिन खिलाड़ियों का रीपोर्टिंग, दस्तावेज सत्यापन और रैंकिंग राउंड संपन्न हुआ। शनिवार को एलिमिनेशन राउंड, सेमीफाइनल और फाइनल के साथ प्रतियोगिता का समापन होगा। पूरा आयोजन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा, आधुनिक प्रशिक्षण और अनुभव दिलाने पर केंद्रित है। इससे पूर्व सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट और सांसद चेंस प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। अब तीरंदाजी और कबड्डी को शामिल कर महोत्सव को और व्यापक रूप दिया जा रहा है। कबड्डी प्रतियोगिता विधानसभा-वार आयोजित की जा रही है। महोत्सव के प्रथम दिन कर्मज मैदान खेलभावना, ऊर्जा और उत्साह से सराबोर रहा। बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों और खिलाड़ियों ने आयोजन को यादगार बना दिया।

मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात: 10 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 10 हजार, महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान



पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1, अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की 10 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये प्रति लाभुक की दर से 1000 करोड़ रुपये की राशि का रिमोट का बटन दबाकर अंतरण किया। इसके पूर्व 1 करोड़ 46 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 14 हजार 600 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है।

स्वाद और पोषण दोनों बेहतर होते हैं और यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी अधिक लाभकारी है। कहा कि जैविक खेती से कृषि की लागत कम होती है और उपज की गुणवत्ता बढ़ती है। इसी क्रम में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत सेमरिया जगन्नाथ वासी गांव में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों द्वारा तैयार की जा रही अरहर बलस्टर खेती का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने खेतों में पहुंचकर किसानों से संवाद किया तथा उनकी समस्याएँ सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। इस मौके पर किसान श्रीधर निपाटी, कमलेश, रमेश, मिथलेश, जगमोहन, राजेश कुमार, नहू प्रसाद, जयगोपाल, कौशलेश सिंह आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

महिला क्रिकेट टीम की बॉलर क्रांति गौड़ का हुआ जोरदार स्वागत



हमीरपुर- भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बॉलर क्रांति गौड़ का शुक्रवार के दिन छनी बुजुर्ग गांव में आमगन पर भव्य स्वागत किया गया।बता दें कि बीते दिनों महिला क्रिकेट का वर्डकप जीतने के बाद भारतीय महिला टीम के होसले बुलंद हैं, इसी दुर्गमिंट में क्रांति गौड़ ने अपनी धारदार गेंदबाजी से पाकिस्तानी टीम के होसले पस्त कर दिए थे।बताते चले कि इंटरनेशनल महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति मध्यप्रदेश के छतरपुर जनपद के चवुवार गांव की मूल निवासिनी हैं जो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं।छनी बुजुर्ग गांव की आकांक्षा पुत्री प्रमोद यादव जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भारत यादव की भतीजी हैं, क्रांति गौड़ की खास दोस्त हैं, जिनके बुलाने पर ही छनी बुजुर्ग गांव आई हुई हैं। आकांक्षा ने बताया कि वह छतरपुर के एक नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं ,और वहीं पर आयोजित साइकिल रेस में भाग लेती रही हैं।बताया कि उसी दौरान एक प्रतियोगिता में क्रांति से मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई।वहीं क्रांति अपने जोरदार स्वागत से भावविभोर हो गई और कहा कि अगर अवसर मिले तो महिलाएं किसी भी कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अपने लक्ष्य पर डटी रहें।

एक्सपेलर में फंसकर युवक का कटा हाँथ, उर्ई मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में हुई मौत



हमीरपुर- मुस्कुरा थाना क्षेत्र जे गहरोली गांव में बीती रात आटा चक्की के स्पेयर में चपेट में आने से एक युवक का हाथ फंसकर कटा गया। परजिन घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र मुस्कुरा ले गए जहां से उसे हालत गंभीर होने पर उर्ई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को सुबह उर्ई पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के गहरोली गांव निवासी मदनचंद्र कुशवाहा ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात्रि 9 बजे उसका पुत्र शैलेंद्र कुमार कुशवाहा उम्र 26 वर्ष अपनी मां के साथ मुस्ताक की चक्की में तेल पिरवाने गया हुआ था, तेल पिछाई के समय खली निकालते समय शैलेंद्र का हाथ स्पेयर की चपेट में आ गया जिससे उसका दांया हाथ धड़ से अलग हो गया। आनन फानन रिक्शे के द्वारा सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र मुस्कुरा लाए जहां हालत गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज उर्ई रेफर कर दिया और मेडिकल कलेज पहुंचने के पूर्व रास्ते में उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को उर्ई पुलिस के पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम कराया इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।

बीएलओ रंजू दुबे की मौत पर सपा नेताओं ने परिजनो से मिलकर जताया शोक

चुनाव आयोग से मुआवजा व नौकरी की मांग
रुद्रपुर। सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम व पोस्ट माझा नारायन पहुंचा, जहाँ उन्होंने ड्यूटी के दौरान निधन हुई बीएलओ रंजू दुबे के पति जगन्नाथ दुबे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सपा परिवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं दुबे परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिना समुचित तैयारी और बेहद कम समय में लागू किए गए एस आई आर कार्य के कारण बीएलओ व बीएलए गंभीर तनाव में हैं, जबकि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में लगन व खेती का कार्य भी चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने अलंघ्यिक संवेदनशील एवं बोझिल जिम्मेदारियों कर्मचारियों पर थोप दी हैं, जो जानलेवा साबित हो रही हैं। सपा जिलाध्यक्ष ने मांग किया कि मृत बीएलओ के परिवार को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, एस आ आर की समय सीमा बढ़ाई जाए तथा अतिरिक्त कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाए। द्धप्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, विली प्रताप यादव, हाफिज शहादत हुसैन, अजीय अमर, हेरेंद्र सिंह त्यागी, संतोष यादव, हसनाथ यादव, रामखेद यादव, सिकंदर यादव, राजनाथ यादव, आदिल, नौशाद, दालिश शेख, विनोद आदि मौजूद रहे।

तिब्बती पहचान पर चीन की नज़र? प्राग घोषणापत्र में दलाई लामा के उत्तराधिकार पर हस्तक्षेप का कड़ा विरोध

आगे कहा गया कि इस अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा इस वर्ष 90 वर्ष के हो गए हैं, जो करुणा वर्ष पहल के तहत विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला एक नील का पत्थर है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर प्राग घोषणापत्र 2025 ने तिब्बती बौद्ध समुदाय को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने के अधिकार पर दृढ़ता से जोर दिया है। फयुल की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम को तिब्बती आध्यात्मिक वंश को नियंत्रित करने के चीन के बढ़ते प्रयासों के प्रति एक फटकार के रूप में देखा जा रहा है। फयुल के अनुसार, प्राग कैसल में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता या विश्वास गठबंधन (आईआरएफबीए) के पांचवें वर्षगांठ

HC पहुंची इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कट दिया मना, अब PTA उठाएगी ये कदम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पाकिस्तान। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी ने अपने भाई की हालत पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उनके परिवार, वकीलों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सदस्यों को चार हफ्तों से ज्यादा समय से उनसे मिलने से रोक दिया है। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी समेत पार्टी के नेताओं की निर्धारित मुलाकातों को भी नकार दिया गया, जिससे खान की मौत की अफवाहें भारत तक फैल गईं। अदियाला जेल के अधिकारियों ने 27 नवंबर (गुरुवार) को इन अफवाहों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और पुष्टि की कि खान हिरासत में हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है और उन्हें चिकित्सा सहायता मिल रही है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने उन्हें जेल में बंद अपने भाई से मिलने की अनुमति न देने के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अदियाला जेल के अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर की। अलीमा खान ने यह याचिका खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य नेताओं की मौजूदगी में दायर की। याचिका में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के 24 मार्च के

लोकपाल ने रायमान खेड़ा में अन्नपूर्णा भवन का किया स्थलीय निरीक्षण, मनरेगा कार्यों की हुई विस्तृत समीक्षा

.....सोशल ऑडिट बैठक में श्रमिकों से लिया फीडबैक, पत्रावलि्यों की हुई जांच, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के विकासखंड मोहनलालगंज स्थित ग्राम पंचायत रायभाना खेड़ा में शुक्रवार को मनरेगा कार्यों के सत्यापन हेतु सोशल ऑडिट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बी0आर0पी0 रेन्नु मिश्रा एवं उनकी टीम की मौजूदगी में मनरेगा श्रमिकों से उनके कार्य और मजदूरी से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। श्रमिकों ने अपनी समस्याओं और अनुभवों को साझा किया, जिसके आधार पर कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन

चरखारी से लौटते समय हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन की तलाश

● बिना हेलमेट चला रह था बाइक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदुलीतार के पास गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल नंदकिशोर पांडेय (36) की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह चरखारी मेला ड्यूटी से वापस अपनी बाइक से हमीरपुर लौट रहे थे। देर रात हुई इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। हेड कांस्टेबल नंदकिशोर पांडेय चित्रकूट के राजपुर थाना क्षेत्र के चिन्हट गांव के निवासी थे। वर्तमान में वह मोहना जनपद के कबरई थाने में तैनात थे और उनका परिवार हमीरपुर पुलिस लाइन में रहता था। गुरुवार को चरखारी मेले में ड्यूटी के बाद वे रात करीब 9:30 बजे अपनी बाइक से हमीरपुर की ओर आ रहे थे।

चंदुलीतार के पास पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नंदकिशोर पांडेय सड़क किनारे गिरकर गंभीर

सम्मेलन के दौरान जारी घोषणापत्र ने इस बात की पुष्टि की कि धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता में तिब्बती बौद्धों को अपने आध्यात्मिक नेताओं को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का अधिकार भी शामिल है। इसमें आगे कहा गया कि इस अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा इस वर्ष 90 वर्ष के हो गए हैं, जो करुणा वर्ष पहल के तहत विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला एक नील का पत्थर है।

तिब्बती बौद्ध धर्म के धार्मिक नेता के रूप में दलाई लामा को 'श्रद्धाजलि' शीर्षक वाले सम्मेलन सत्र को संबोधित करते हुए, सीटीए के अध्यक्ष पेनपा त्सेरिंग ने चेतावनी दी कि पुनर्जन्म प्रक्रिया में चीन के हस्तक्षेप का उद्देश्य तिब्बती बौद्ध धर्म के भविष्य को प्रभावित करना है। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार तिब्बती लोगों को नियंत्रित करने के लिए एक कठपुतली दलाई लामा को नियुक्त करना चाहती है। त्सेरिंग ने अमेरिका द्वारा पारित 2002 के तिब्बत नीति अधिनियम का भी उल्लेख किया, जो चीन को तिब्बत में वास्तविक स्वायत्तता के लिए दलाई लामा के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।



आदेश का जिक्र किया गया है, जिसमें अदालत ने 73 वर्षीय खान से सप्ताह में दो बार मुलाकात करने की अनुमति दी थी। खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। इसमें कहा गया है कि अलीमा ने अदालत के आदेशों का जानबूझकर पालन न करने की वजह से अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है, विशेष रूप से अधिकारियों द्वारा उन्हें खान से मिलने की अनुमति न देने के संबंध में। याचिका में कहा गया कि मॉलवार और बृहस्पतिवार को मुलाकात की अनुमति के निर्देशों के बावजूद 'प्रतिवादियों' ने इसका पालन नहीं किया और न ही इसे उनका सलाहमती, कानूनी अधिकारों और मानवीय व्यवहार को लेकर बेहद चिंतित रही हैं। इसमें जिन लोगों को नामजद किया गया है उनमें अदियाला जेल अधीक्षक अब्दुल गफूर अंजुम, सदर बेरोनी थाने के प्रभारी अधिकारी राजा एजाज अजीम, संघीय गृह सचिव कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद खुर्रम आगा और पंजाब गृह विभाग के सचिव नूरूल अमीन शामिल हैं।



किया गया। इसी क्रम में लोकपाल डॉक्टर आर.आर. जैसवाल ने ग्राम पंचायत द्वारा संचालित अन्नपूर्णा भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, उपयोगिता और अभिलेखों की स्थिति का गहन परीक्षण किया। लोकपाल ने पत्रावलियों का औचक निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए, ताकि भविष्य में कार्य और अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ

देश विदेश

आईएसएस संतोष वर्मा की ब्राम्हण महिलाओं पर टिप्पणी का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, कार्यवाही के निर्देश



उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को, सात लोकतांत्रिक देशों ने संयुक्त रूप से तिब्बती लोगों के अपने अगले आध्यात्मिक नेता को चुनने के अधिकार के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने आईआरएफबीए से एक विज्ञप्ति जारी करने का आग्रह किया जो इन सिद्धांतों को प्रतिध्वनित करे और चीन के हस्तक्षेप के विरुद्ध वैश्विक सहमति को सुदृढ़ करे, जैसा कि फयुल ने रेखांकित किया है। इस उच्च-स्तरीय सभा में चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल, संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत नाज़िला घनेया और मानवाधिकार अधिकवक्ता मुबारक बाला शामिल थे। घोषणा का स्वागत करते हुए, सीटीए प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने कहा कि यह हमारी आध्यात्मिक परंपराओं की एक महत्वपूर्ण पुष्टि और राज्य के हस्तक्षेप की स्पष्ट अस्वीकृति है।

रोजगार मेला में 53 युवाओं को मिला रोजगार



हमीरपुर- मुस्कुरा विकासखण्ड क्षेत्र के लोदीपुर-जलालपुर स्थित प्राइवेट औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण संस्थान(आईटीआई) में शुक्रवार के दिन जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया।सुबह लगभग साढ़े ग्यारह बजे शुरू हुए रोजगार मेला में कुल 78 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया जिनमें से साक्षात्कार के बाद 53 युवाओं को मेला में प्रतिभाग करने वाली कंपनियों ने जॉब ऑफर किया।कौशल आईटीआई के प्रबंधक उमेश सक्सेना ने बताया कि रोजगार मेला में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन कानपुर ,बुटर मैन पॉवर सोलुशन प्राोलि0 गौतमबुद्ध नगर ,एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हमीरपुर और के0जी0बी0एस0 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिभाग किया।प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन कानपुर ने 9, बुटर मैन पॉवर सोलुशन प्राोलि0 गौतमबुद्ध नगर ने 17, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हमीरपुर ने 6 और के0जी0 बी0एस0 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 21 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर प्लेसमेंट दिया।रोजगार मेला में लाइफ इंश्योरेंस डेवलपमेंट मैनेजर विष्णुशरण मिश्र व श्रद्धा द्विवेदी ,प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के पुष्पेंद्र सिंह, बुटर मैन पॉवर सॉल्यूशन के ब्रजेश कुमार और के0जी0बी0एस0 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सतीश कुमार मौजूद रहे।



संचालित हो सके। इस मौके पर ग्राम प्रधान सुमन रावत, पंचायत सचिव अनीता मिश्रा, इंजीनियर लालचतहादुर पाण्डेय, ग्राम रोजगार सेवक विनीत मिश्रा, पंचायत सहायक रूबी कन्नीजिया, सोशल आडिट टीम के सदस्यों मनोहर लाल, राजकुमार, सुनीता देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन और ग्रामीणों के बीच संवाद स्थापित हुआ, जिससे मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक सुधार की संभावनाएँ बनीं।

दलाली का काम करने वाले भी बन बैठे पत्रकार

● पत्रकारिता छेत्र शहडोल संगम के लिए बड़ी दु:ख की बात

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल दिनेश चौधरी

शहडोल में पत्रकारों की एक अलग ही मिशाल हैं जो अपने पत्रकार जगत की मध्यप्रदेश सहित भारत के लिए अलग ही पहचान से जाना जाता हैं। लेकिन शहडोल जिले में बढ़ते अपराधों को झुंपाने के लिए पत्रकारिता की चोला ओढ़ पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। आपको बता दे कि गुड्डन भईया का सफर एक आरटीओ एजेंट के रूप से शुरू हुई, फिर अधिकारी से मधुर संबंध बनाने के बाद पूरी व्यवस्था की जवाबदारी ली और व्यवस्थाओं पर खरे उतरे गए और पूरे जिले की परिवहन की आफ रिकॉर्ड हलाल अधिकारी बन वसूली चालू हुई। इस सफर से सफल होकर एक पुलिस विभाग के अधिकारी से मधुर संबंध बनाकर दी गई है। जानकारी के मुताबिक वह बगैर हेलमेट लगाए बाइक चला रहे थे।

आईएसएस संतोष वर्मा की ब्राम्हण महिलाओं पर टिप्पणी का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, कार्यवाही के निर्देश

हमीरपुर- भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आईएसएस संतोष वर्मा के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एम.खान एवं जिला प्रमुख युवा संरक्षण विकास सिंह टोन् ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी ने शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। संगठन ने इसे न सिर्फ सामाजिक गरिमा का उल्लंघन बताया, बल्कि महिलाओं की मर्यादा के विरुद्ध गंभीर टिप्पणी बताते हुए मामले को आयोग तक पहुंचाया। आयोग ने शिकायत की प्रारंभिक समीक्षा के बाद संबंधित विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी वर्ग, समुदाय या महिलाओं के सम्मान से संबंधित मामलों में कड़ी संवेदनशीलता बरती जाएगी। संगठन सीटीए प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने कहा कि पीड़ित समाज के लिए राहत बताते हुए कहा कि वे मामले का पीछ तब तक करेंगे जब तक आरोपी पर उचित कार्रवाई नहीं होती।

श्रीभूमि जिले में सोनबिल सिंधुआ फुलतली में एक बोरे में एक शव मिलने की सनसनीखेज घटना घटी

● परिवार का आरोप है कि यह एक सुनियोजित हत्या किया गया।

उन्होंने मांग की कि प्रशासन इस जघन्य हत्या की उचित जांच करके दोषियों की पहचान करे और उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाए।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: श्रीभूमि जिले के सोनबिल-सिंचवा फुलतली इलाके में आज 28 नवंबर (शुक्रवार) सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। मृतक की पहचान शरीफ उद्दीन एजुकेशन फाउंडेशन कानपुर ने 9, बुटर मैन पॉवर सोलुशन प्राोलि0 गौतमबुद्ध नगर ने 17, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हमीरपुर ने 6 और के0जी0 बी0एस0 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 21 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर प्लेसमेंट दिया।रोजगार मेला में लाइफ इंश्योरेंस डेवलपमेंट मैनेजर विष्णुशरण मिश्र व श्रद्धा द्विवेदी ,प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के पुष्पेंद्र सिंह, बुटर मैन पॉवर सॉल्यूशन के ब्रजेश कुमार और के0जी0बी0एस0 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सतीश कुमार मौजूद रहे।

जिला निवाचन अधिकारी ने एस.आई.आर. कार्य में जन-प्रतिनिधियों से सहयोग करने की अपील

● वर्ष 2003 की मतदाता सूची की जानकारी

https://@Voter-eci-gov-in csolkbV वेवसाइट पर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल दिनेश चौधरी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) 2026 के तहत कार्य निरंतर प्रगति पर है। एसआईआर के बेहतर क्रियान्वन एवं प्रगति की समीक्षा हेतु जिला स्तरिय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. केदार सिंह, जन-प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थित में आयोजित की गई। कलेक्टर ने जिले के जन-प्रतिनिधियों को एसआईआर की प्रगति से अवगत कराते हुए कहा कि एसआईआर कार्य में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, स्व-

बेबस परिवारों की हँसी लौटाने के लिए कुटीर उद्योग स्थापना में व्यक्तिगत पहल पर पूर्व एडीसी निलमणि दास की आर्थिक मदद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: श्रीभूमि जिले के पाथारकांडी विधान सभा अंतर्गत फाकुआ गांव के निवासी दीपक दास पुरकायस्थ पिता स्व. पल्टू दास पुरकायस्थ को कुटीर उद्योग स्थापना के उद्देश्य से आर्थिक सहयोग पूर्व एडीसी निलमणि दास ने दिया। नित्यखाने-पीने वाले दीपक दास पुरकायस्थ से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 2019 में उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से 70 हजार रुपये खर्च करके दलमूट फैक्ट्री बनाई थी। वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले होने के कारण परिवार के चिकित्सा और घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए यह कुटीर उद्योग बंद करना पड़ा।

इसके अलावा, उनका पिता जीवित रहते हुए विश्वकर्मा परियोजना के तहत फाकुआ गांव की पीपनबी शाखा से एक लाख रुपये का ऋण लिया था। ऐसी परिस्थितियों में पिता की मृत्यु से वे दिशाहीन हो गए। अंततः फाकुआ गांव के निवासी प्रताप नमःशुद्र की मदद से समाजसेवी एवं पूर्व एडीसी निलमणि दास के संरक्षण में आए। हालांकि उनकी मदद से सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 'डेट्र सर्टिफिकेट' लाने में सहायता का हाथ बढ़ाया गया। सहयोग का



परिवार के सदस्यों ने उसे फोन किया और पाया कि वह बंद है।

रात भर दूढ़ने के बाद भी शरीफ और का कोई अता-पता नहीं चला और उस अभिशात रात के अंत के बाद आज सुबह होते ही सिंगुआ फूलतली गांव के पुल के पास एक बोरा पड़ा देख राहगीरों को संदेह हुआ। पलभर में खबर फैलते ही हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिले के रामकृष्णनगर थाना और कालीबाड़ी पुलिस घटनास्थल पर आकर शव बरामद करते हैं, जिसे परिवार के सदस्य पहचानते हैं। परिवार का आरोप है कि यह एक योजनाबद्ध हत्या है। मृतक की पत्नी रीना बेगम समेत परिवार का दावा है कि कल पूरे दिन एक स्थानीय व्यक्ति शरीफ को दूढ़ रहा था। रात को घर लौटने के बाद भी



हाथ बढ़ाने के साथ-साथ असहाय परिवारों की हँसी लौटाने के लिए डालमूट फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने हेतु गत 27 नवंबर को अपने आवास पर व्यक्तिगत रूप से हत्ती सहायता प्रदान की। इसी तरह, लोगों के बीच नोंदंर नगर गांव के निवासी बिज्जरपाटे परम आनंद दास की मृत्यु पर उनकी पत्नी आरती दास को 08-12-2022 को सरकारी तौर पर 4 लाख रुपये प्राप्त कराने में भी मदद की। इसका Momo no-KRR38/Lightning/Pt/2022/13-A.A/c No-1363010232586 है। इसके अलावा वर्तमान रामकृष्णनगर और पाथारकंडी विधान सभा के 56 घर फकुआ-नया नवीन गांव- बाजार फकुआ के तीन गांवों के लगभग 250 परिवारों के डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्मर बदलने में मदद करने पर उक्त क्षेत्र के लोग आभार व्यक्त किया।

श्रीभूमि जिले में सोनबिल सिंधुआ फुलतली में एक बोरे में एक शव मिलने की सनसनीखेज घटना घटी



उस व्यक्ति ने फोन कर बुलाया और ले गया। सिर और गर्दन पर धारदार हथियार के वार से यह स्पष्ट रूप से बेरहम हत्या है। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को गांव से कुछ किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। स्थानीय निवासियों का भी अनुमान है यह पूर्वनिर्धारित हत्या है। सामाजिक नेताओं का दावा है दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। घटनास्थल पर दौड़े आनंदपुर जीपी के समाजसेवी जयदेव दास, बुद्ध दास, बिजित दास, मिसबाहुल रहमान, ताज उद्दीन सहित कई अन्य लोग। उन्होंने प्रशासन की उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। यह एक घोर हत्या है। उचित जांच के माध्यम से दोषियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र कठोर सजा के दायरे में लाना होगा।

जिला निवाचन अधिकारी ने एस.आई.आर. कार्य में जन-प्रतिनिधियों से सहयोग करने की अपील

● वर्ष 2003 की मतदाता सूची की जानकारी

https://@Voter-eci-gov-in csolkbV वेवसाइट पर

सहायता समूह की महिलाओ नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डियूटी लेवाई गई है। उन्होंने कि बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्रक एकत्रित कर बीएलओ ऐप में डिजिटलाईजेशन कार्य मैपिंग के साथ किया जा रहा है। इस कार्य में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जन-प्रतिनिधियों से सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान सूची के पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी, तथ्यपरक तथा शुटिरहित बनाने के लिए यह कार्य निरंतर प्रगति पर है। एसआईआर के बेहतर क्रियान्वन एवं प्रगति की समीक्षा हेतु जिला स्तरिय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. केदार सिंह, जन-प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थित में आयोजित की गई। कलेक्टर ने जिले के जन-प्रतिनिधियों को एसआईआर की प्रगति से अवगत कराते हुए कहा कि एसआईआर कार्य में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, स्व-

प्रसव के बाद जच्चा की मौत, परिजनों में आक्रोश



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- के बाद महिला की मौत परिजनों में कोहराम मच गया और गुस्सा परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराने की मांग पर पड़चुने महिला के मायके पक्ष के लोगों ने लगाते हुए हंगामा किया। ललपुरा थाना क्षेत्र के उजनेड़ी गांव की गायत्री (24वर्ष) पति विनय गुरुवार को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने सुबह करीब 7 बजे पौधिया के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। करीब 4 घंटे बाद महिला ने लड़के को जन्म दिया और सही सलामत रही।लगभग दो घंटे बाद महिला ने पेट व बदन दर्द होने की बात पौधिया एएमम कल्यान सिंह को बताई।एमम ने प्राथमिक



उपचार के बाद महिला को हमीरपुर जिला अस्पताल रिफर कर दिया। जहाँ जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।उधर सूचना पर पहुंचे महिला के मायके पक्ष के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग पर शुक्रवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के पति विनय ने बताया पत्नी की नामल डिलीवरी में एक लड़के को जन्म दिया है बच्चा हमीरपुर जिला अस्पताल थाती है बच्चा ठीक है।उधर ललपुरा थाना प्रभारी राकेश कुमार सरोज ने बताया भौतिक सूचना के आधार पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया।